राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उतरांचल, उतराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 23 अगस्त 2026 वर्ष-9,अंक-201 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मिलेगी अभेद्य सुरक्षा- शाह ने त्रिकोणीय ग्रिड की घोषणा की

सिलीगुड़ी ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की घोषणा की। सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के उत्तर बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में, उन्होंने करीब 189 करोड़ की विभिन्न प्रशासनिक और आवासीय परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है, जो पूर्वोत्तर सहित आठ राज्यों को जोड़ता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए, उन्होंने धुबरी (असम), किशनगंज (बिहार) और चोपड़ा (पश्चिम बंगाल) में तीन नए सैन्य गैरीसन (सैन्य छावनी) वाले एक रक्षा त्रिकोणीय ग्रिड के गठन की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री शाह ने स्पष्ट किया कि यह ग्रिड क्षेत्र में निगरानी, सैन्य उपस्थिति और प्रशासनिक नियंत्रण को काफी हद तक मजबूत करेगा, जिससे किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सकेगा। इस कार्यक्रम में गृह मंत्रालय और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। शाह ने 1965 में स्थापित एसएसबी की भूमिका की सराहना की, जो 2001 से भारत-नेपाल और 2004 से भारत-भूटान सीमाओं की कुशलता से सुरक्षा कर रही है। उन्होंने क्षेत्र में तीस्ता प्रहार जैसी सैन्य अभ्यासों के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। गृह मंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को भी दोहराया, जिसके लिए उन्होंने विनिर्माण, रक्षा शक्ति, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सप्त धारा (सात मुख्य स्तंभों) का उल्लेख किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों के समाधान में हुई प्रगति का भी जिक्र किया।

भारतीय वैज्ञानिकों का अभिनव कदम- कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर खत्म करने वाली स्मार्ट दवा ईजाद

आरके-251 केवल कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को निशाना बनाएगी

नई दिल्ली।

भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर के उपचार में एक क्रांतिकारी सफलता हासिल की है। उन्होंने आरके-251 नामक एक ऐसी स्मार्ट दवा विकसित की है जो केवल कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को निशाना बनाएगी, जबकि शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह खोज कैंसर के अधिक लक्षित और कम हानिकारक उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे कीमोथेरेपी के मौजूदा विकल्पों से बेहतर माना जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यह प्रभावित कोशिकाओं के साथ-साथ कुछ स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है। आरके-251 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि शरीर में रहते हुए यह अपेक्षाकृत निष्क्रिय बनी रहती है। यह दवा कैंसर कोशिकाओं के विशिष्ट रासायनिक वातावरण में पहुंचने पर ही सक्रिय होती है। अनेक कैंसर कोशिकाओं में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज (आरओएस) का स्तर सामान्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक होता है, और वैज्ञानिकों ने इसी अंतर का लाभ उठाने की कोशिश की है। आरओएस के संपर्क में आने पर, आरके-251 से एनबीडीएचईएक्स नामक एक सक्रिय यौगिक निकलता है। यह यौगिक कैंसर कोशिकाओं में मौजूद जीएसटीपी1 जैसे प्रोटीन को निशाना बनाता है, जो कोशिकाओं के जीवित रहने और दवा प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे एक ऐसे मॉलिक्यूलर स्विच की तरह समझा जा सकता है जो केवल कैंसर कोशिका के माहौल में पहुंचने के बाद ही सक्रिय होता है। इस महत्वपूर्ण शोध का नेतृत्व इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएएसटी) के डॉ. असिस बाला और आईआईटी गुवाहाटी के डॉ. कृष्णा पी. भाबक ने किया। यह शोध आईएएसटी और आईआईटी गुवाहाटी के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है और इसके निष्कर्ष प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में प्रकाशित हुए हैं।

रिवारवाद के कारण मुश्किल घड़ी में नहीं टूटी सपा - अखिलेश यादव

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने परिवारवाद के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देकर कहा कि इसके कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं। उन्होंने कहा कि जब कई राजनीतिक दल कठिन परिस्थितियों में टूट गए, तब समाजवादी पार्टी एकजुट बनी रही। इसके पीछे एक कारण यह था कि पार्टी के पांच सांसद एक ही परिवार से थे। इसके अलावा कुछ मुस्लिम सांसद और समर्पित समाजवादी नेता भी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिससे संगठन को ताकत मिली। अखिलेश ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधकर कहा कि आज सच बोलने वालों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा और अन्य बुनियादी मुद्दों को उठाने वालों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में इंटरनेट, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसलिए नई पीढ़ी की आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियां बनानी होंगी।

अंतरिक्ष क्रांति की ओर भारत- इसरो का रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस

- उत्पादन निजी हाथों में

हैदराबाद।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अभूतपूर्व ढांचागत बदलाव की दहलीज पर है। संगठन अपने पारंपरिक कार्यों, जैसे रॉकेट और सामान्य उपग्रहों के निर्माण की जिम्मेदारी, धीरे-धीरे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सौंपने की तैयारी में है। इस रणनीतिक कदम के साथ, इसरो का पूरा ध्यान अब पूरी तरह से रिसर्च और डेवलपमेंट (आरएंडडी) पर केंद्रित रहेगा। जहाँ वे उन्नत तकनीकों, वैज्ञानिक अभियानों और अंतरिक्ष अवसंरचना के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

इन-स्पेस के चेयरमैन डॉ.पवन गोयनका ने बड़े बदलाव की पुष्टि कर बताया कि रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण का पूरा कारोबार अब निजी कंपनियों को हस्तांतरित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत, स्मॉल सैटेलाइट लांच व्हीकल (एसएसएलवी) की तकनीक और उत्पादन अधिकार पहले ही एक बोली प्रक्रिया के माध्यम से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को सौंपे जा चुके हैं। इस महत्वपूर्ण बदलाव का मुख्य उद्देश्य भारत की बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने 2033 तक देश की स्पेस इकोनॉमी को वर्तमान के 8 अरब डॉलर से बढ़ाकर 44 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

इस दिशा में प्रगति जारी है, इसरो अब तक 120 से अधिक तकनीकें निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर चुका है। इससे एक इसतरह के वाणिज्यिक मॉडल को बढ़ावा मिलेगा, जहाँ निजी कंपनियाँ स्वयं के उपग्रहों का निर्माण कर डेटा और सेवाओं के माध्यम से राजस्व अर्जित कर सकेंगी। जबकि इसरो का पूरा ध्यान अधिक जटिल और दूरगामी वैज्ञानिक अभियानों पर बना रहेगा।

डॉ.गोयनका ने बताया कि यह बदलाव गति पकड़ रहा है और

अगले चरणों में भारत के सबसे शक्तिशाली ऑपरेशनल रॉकेट, लांच व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम-3) और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) के निर्माण की कमान भी पूरी तरह से निजी कंपनियों को सौंपी जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार अगले चार से पांच महीनों में एक नए लॉन्च सेंटर के संचालन के लिए निजी ऑपरेटर को अंतिम रूप देने की योजना बना रही है।

पाकिस्तान से चीनी नहीं खरीदेगा भारत.....केंद्र सरकार ने किया साफ

नई दिल्ली ।

भारत ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए कच्चे चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने के बावजूद पाकिस्तान से चीनी लेने से साफ इंकार किया है। यह फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वहां के व्यापारी भारत में चीनी बेचने को बेताब दिख रहे थे। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि मई 2019 से इस्लामाबाद के साथ व्यापार पर लगी मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी और उनमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेजी और आपूर्ति की चिंताओं के मद्देनजर, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है।

इस घोषणा के बाद, पाकिस्तान के चीनी उद्योग ने अपनी सरकार से भारत को चीनी निर्यात करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया था, खासकर तब जब इस्लामाबाद भी चीनी का निर्यात बढ़ाना चाहता है। यहां तक कि पाकिस्तान ने हाल ही में 1.05 लाख टन चीनी बेचने के लिए एक वैश्विक टेंडर भी जारी किया

था।

हालांकि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख और नीति स्पष्ट है, और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने जोर दिया कि भारत को अगर चीनी की जरूरत है, तब वैश्विक बाजार में काफी अन्य विकल्प मौजूद हैं, और भारत को पाकिस्तान से चीनी लेने की आवश्यकता नहीं है।

जेन-जी तक पहुंच बढ़ाने के लिए बीजेपी की नई टीम गठित

युवा संवाद अभियान होगा शुरू

नई दिल्ली ।

भारतीय जनता पार्टी ने युवा मतदाताओं, विशेषकर जेन-जी (जेन-जी) वर्ग से जुड़ाव मजबूत करने के लिए विशेष टीम का गठन किया है। इस नई टीम में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हैं। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कांग्रेस द्वारा अपने कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के केवल दो पैराग्राफ गाने के निर्णय के विरोध में प्रस्ताव भी पारित किया। भाजपा ने फैसले की आलोचना कर राष्ट्रभावना के विपरीत बताया। पार्टी की नई टीम ने शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा मुख्यालय में मुलाकात का कार्यक्रम भी तय किया।

भाजपा की यह टीम 14 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को जोड़ने के लिए देशभर में 'युवा संवाद' अभियान चलाएगी। अभियान के तहत संवाद, चर्चा और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं की सोच, अपेक्षाओं, चिंताओं और जरूरतों को समझा जा सके।

साथ ही उन्हें पार्टी नेताओं के साथ सीधे संवाद का अवसर भी मिलेगा।

जंतर मंतर पर जातिगत आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर-आरक्षित श्रेणी के लोगों और युवाओं ने जाति-आधारित आरक्षण प्रणाली और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकारी सहायता, छात्रवृत्ति और फीस में छूट जैसे लाभ जातिगत पहचान के बजाय पूरी तरह से आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलाना चाहिए।

विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एससी/एसटी एक्ट को रद्द करने की अपील की। उनका तर्क था कि इस एक्ट का लाभ हमेशा समाज के सबसे वंचित वर्गों तक नहीं पहुँचता और इसका दुरुपयोग व्यक्तियों के खिलाफ हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।

इसके साथ ही, प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण में क्रीमी-लेयर का नियम लागू करने और दशकों पुराने आरक्षण प्रावधानों की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखकर समीक्षा करने की भी मांग की। उनका कहना था कि हालात काफी बदल गए हैं और अब आर्थिक पिछड़ेपन को बिना किसी भेदभाव के हल करने पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

यह विरोध प्रदर्शन आरक्षण सुधार आंदोलन के बैनर तले नीट के छात्र हर्ष दुबे के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान की जनरल सेना, चाणक्य सेना और करणी सेना जैसे संगठन भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी, जिनमें मुख्य रूप से युवा पुरुष थे, अपने

हाथों में भगवा झंडे और गरीबों के लिए आरक्षण, जाति के लिए नहीं जैसे नारे लिखे प्लेकार्ड लिए हुए थे। हालांकि, यह प्रदर्शन बिना अनुमति के किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की और शाम को कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आयोजकों को रामलीला मैदान में 500 लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मिली थी, जंतर मंतर पर नहीं।

दिल्ली में स्वाइन फ्लू का विकराल रूप,मामले तेजी से बढ़े

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में 114 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1777 हो गई है। यह आंकड़ा बीते साल के 229 मामलों की तुलना में सात से आठ गुना अधिक है, जो चिंताजनक स्थिति को दिखाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन हर कुछ सालों में बदल जाता है, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। एसी का बढ़ता इस्तेमाल, मॉनसून के दौरान मौसम में लगातार बदलाव, घरों और बंद जगहों पर लोगों की भीड़ तथा हवा के उचित संचार की कमी भी संक्रमण के तेजी से फैलने में सहायक होती है। एम्स के डॉ. नीरज निश्चल ने कोविड की तरह ही एक वायरल इफेंक्शन बताया है, जिसके बचाव के लिए हैंड हाइजीन और मास्क का उपयोग बेहद प्रभावी उपाय हैं। इस साल स्वाइन फ्लू छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। आम जनता के साथ-साथ एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों के डॉक्टर और स्टाफ भी इससे संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी बुखार के ज्यादातर मरीजों में स्वाइन फ्लू ही मिल रहा है। यदि किसी को तीन से चार दिनों तक बुखार रहता है,तब उन्हें तुरंत जांच करानी चाहिए। एक अन्य डॉक्टर के मुताबिक, भले ही रिकवरी दर बेहतर है, लेकिन कम प्रतिरक्षा वाले लोगों में बीमारी गंभीर रूप ले रही है, इसकारण कई मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर पर भी हैं।

वैज्ञानिकों ने की गैलेक्सी में तीन सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहचान

वाशिंगटन ।

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ही गैलेक्सी में तीन सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहचान की है। शोध के अनुसार, यह गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 12.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका नाम जे0148-4214 है। इतनी अधिक दूरी होने के कारण वैज्ञानिक इस गैलेक्सी को बिग बैंग के लगभग 1.2 अरब वर्ष बाद की अवस्था में देख रहे हैं, जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास को समझने में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। यह खोज जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल फिजिक्स के शोधकर्ताओं ने की है। शोधकर्ताओं ने इन तीनों ब्लैक होल की पहचान उनके विशेष स्पेक्ट्रल संकेतों और हाइड्रोजन उत्सर्जन रेखाओं के विश्लेषण के आधार पर की। गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद दो ब्लैक होल एक-दूसरे से केवल 620 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं, जबकि तीसरा ब्लैक होल केंद्र से लगभग 5,500 प्रकाश वर्ष दूर बाहरी हिस्से में पाया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाइड्रोजन गैस के अत्यधिक वेग से घूमने के कारण उत्पन्न संकेतों ने इनकी सटीक स्थिति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस खोज के लिए शोध दल ने स्पेक्ट्रो-एस्ट्रोमेट्री तकनीक का उपयोग किया, जिसके माध्यम से गैलेक्सी के भीतर उत्सर्जन रेखाओं में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का अत्यंत सटीक विश्लेषण किया गया। इसमें जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के एनआईआरस्पेक-आईएफएस उपकरण ने निर्णायक भूमिका निभाई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आधुनिक तकनीक के बिना संभवतः केवल एक ब्लैक होल की ही पहचान हो पाती। अध्ययन के अनुसार, इन तीनों ब्लैक होल का द्रव्यमान क्रमशः लगभग 8 करोड़, 6 लाख और 20 लाख सौर द्रव्यमान के बराबर है। इनमें से 6 लाख सौर द्रव्यमान वाला ब्लैक होल अत्यंत तेज गति से अपने आसपास के पदार्थ को निगल रहा है और उसकी वृद्धि सामान्य सैद्धांतिक सीमा से भी अधिक बताई गई है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद दोनों विशाल ब्लैक होल अगले कुछ करोड़ वर्षों में आपस में विलय कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वीय तरंगें भविष्य में अंतरिक्ष वेधशालाओं के लिए महत्वपूर्ण संकेत साबित हो सकती हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार, गैलेक्सी के बाहरी हिस्से में मिला तीसरा ब्लैक होल इस खोज का सबसे रोचक पहलू है। माना जा रहा है कि यह किसी प्राचीन आकाशगंगीय टक्कर का अवशेष हो सकता है या फिर किसी शक्तिशाली गुरुत्वीय प्रभाव के

कारण केंद्र से बाहर निकल गया हो। यह भी संभव है कि वह धीरे-धीरे दोबारा गैलेक्सी के केंद्र की ओर बढ़ रहा हो। यह शोध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में प्रकाशित हुआ है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पेपर लीक से पटना राजभवन तक, छात्रों के गुस्से में छिपी राजनीति का सच

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल किसी एक पार्टी की जीत या हार का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बिहार का युवा परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कर सकता है? क्या उसे यह विश्वास है कि उसकी मेहनत का परिणाम निष्पक्ष तरीके से मिलेगा? और क्या सरकार तथा विपक्ष दोनों इस सवाल का राजनीतिक जवाब देने के बजाय प्रशासनिक समाधान देने को तैयार हैं?

(लेखक-कांतिलाल मांडोत)

बिहार की राजनीति में छात्रों, परीक्षा और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर सड़क पर है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने पटना में जेपी गोलंबर से राजभवन तक मार्च निकाला। करीब पांच किलोमीटर के इस मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रास्ते में बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में तेजस्वी यादव तथा मीसा भारती को हिरासत में लिया गया। करीब एक घंटे बाद तेजस्वी को छोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की तथा कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस की ओर पानी की बोतलें फेंके जाने की घटनाएं भी सामने आईं।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक राजनीतिक मार्च के रूप में देखना अधूरा होगा। इसके पीछे बिहार के छात्रों का असंतोष, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठते सवाल, रोजगार की चिंता और उससे कहीं बड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छिपी हुई है। असली सवाल यही है कि आखिर पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा हर राजनीतिक दल इतनी ताकत से क्यों उठा रहा है? क्या यह केवल छात्रों के भविष्य की चिंता है या इसके पीछे चुनावी राजनीति का भी बड़ा गणित काम कर रहा है?

सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से एके-47 से फायरिंग का मामला इस बहस को और गंभीर बना चुका है। उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने एके-47 से गोलियां चलाईं। एक अन्य जवान के सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग करने की बात भी सामने आई। इसके बाद मामला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया। राजद सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया और बाद में प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव हुए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में एके-47 से चार राउंड हवाई फायरिंग होने की बात स्वीकार की, लेकिन यह भी कहा कि छात्रों को एके-47 की गोली नहीं लगी।

यहीं से मामले का सबसे बड़ा सस्पेंस सामने आता है। एक तरफ पुलिस फायरिंग की घटना स्वीकार की जाती है, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि छात्रों को गोली नहीं लगी। राजनीतिक दल इसे छात्रों पर गोली चलाने की घटना के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि सरकार फायरिंग को अलग संदर्भ में रख रही है। इसी अंतर ने मामले को केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं रहने दिया, बल्कि इसे सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष का मुद्दा बना दिया है।

तेजस्वी यादव का राजभवन मार्च इसी राजनीतिक माहौल का विस्तार है। उन्होंने छात्रों के समर्थन में संघर्ष जारी रखने और युवाओं को रोजगार मिलने तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। उनका यह कहना कि वे जेल से डरने वाले नहीं हैं और सत्ता में आया व्यक्ति एक दिन सत्ता से बाहर जाता है, बताता है कि आंदोलन को राजद केवल छात्र मुद्दे तक सीमित नहीं रखना चाहता। पार्टी इसे सरकार की कार्यशैली, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ व्यापक राजनीतिक अभियान में बदलना चाहती है।

दूसरी ओर, सत्ता पक्ष के लिए यह मुद्दा कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। बिहार में युवाओं की बड़ी आबादी प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहती है। परीक्षा की तारीखों में बदलाव, कथित पेपर लीक, नकल, भर्ती प्रक्रिया में देरी या परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल सीधे युवा मतदाता की चिंता से जुड़ते हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस वर्ग की नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं है।

यही वह जगह है जहां पेपर लीक का मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद ताकतवर बन जाता है। छात्र जब परीक्षा में बैठता है तो उसके सामने केवल एक प्रश्नपत्र नहीं होता, बल्कि वर्षों की मेहनत, परिवार की उम्मीद और नौकरी पाने का सपना होता है। यदि उसे लगता है कि परीक्षा की व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है, तो उसकी नाराजगी स्वाभाविक रूप से सरकार की ओर जाती है। विपक्ष इसी नाराजगी को राजनीतिक आवाज देता है।

लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विपक्ष के लिए पेपर लीक और रोजगार का मुद्दा सरकार को घेरने का सबसे प्रभावी हथियार है, क्योंकि इसमें जाति, क्षेत्र या पार्टी की विचारधारा से ज्यादा युवा का भविष्य केंद्र में दिखाई देता है। सरकार के लिए यही मुद्दा सबसे संवेदनशील इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था की किसी भी कमी का राजनीतिक नुकसान सीधे युवाओं के बीच हो सकता है। यही कारण है कि पेपर लीक का मुद्दा एक परीक्षा केंद्र से निकलकर विधानसभा, संसद, सड़क और अब राजभवन तक पहुंच जाता है।

इस राजनीति में छात्रों की वास्तविक परेशानी और राजनीतिक दलों का हित एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। छात्र न्याय और पारदर्शिता चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल उसी मांग को अपने पक्ष में जनसमर्थन जुटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक बयानबाजी असली समाधान से बड़ी हो जाती है। यदि किसी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान, समयबद्ध कार्रवाई और प्रभावित अभ्यर्थियों के भविष्य की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। केवल आरोप-प्रत्यारोप से छात्रों की समस्या हल नहीं होगी।

पटना के मार्च ने यह भी दिखाया कि राजनीतिक प्रदर्शन का असर आम जनता पर पड़ता है। मार्च के कारण शहर के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात बाधित हुआ और जाम में एंबुलेंस के फंसने की तस्वीरें सामने आईं। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के साथ सार्वजनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान हो और पुलिस कार्रवाई आवश्यकता से अधिक कठोर न हो।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल किसी एक पार्टी की जीत या हार का नहीं है। सवाल यह है कि क्या बिहार का युवा परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कर सकता है? क्या उसे यह विश्वास है कि उसकी मेहनत का परिणाम निष्पक्ष तरीके से मिलेगा? और क्या सरकार तथा विपक्ष दोनों इस सवाल का राजनीतिक जवाब देने के बजाय प्रशासनिक समाधान देने को तैयार हैं?

पेपर लीक का मुद्दा इसलिए बार-बार लौट रहा है क्योंकि यह केवल प्रश्नपत्र की सुरक्षा का मामला नहीं है। यह व्यवस्था में विश्वास का सवाल है। जब तक परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुरक्षित और जवाबदेह नहीं बनेगी, तब तक हर नई परीक्षा के साथ पुराने सवाल फिर खड़े होंगे।

विपक्ष उन्हें सरकार के खिलाफ उठाएगा, सरकार अपने बचाव में जवाब देगी और सबसे ज्यादा असमंजस में वही छात्र रहेगा जिसने महीनों या वर्षों तक तैयारी की है।

बिहार में राजभवन मार्च ने फिलहाल राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने इसे छात्रों और युवाओं की लड़ाई बताया है, जबकि सरकार के सामने कानून-व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था दोनों को लेकर सवाल हैं। सीवान की फायरिंग ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। अब जनता की नजर केवल राजनीतिक भाषणों पर नहीं, बल्कि जांच और कार्रवाई के परिणाम पर होगी।

इस पूरे विवाद का पर्दाफाश यही है कि पेपर लीक आज राजनीति का सुविधाजनक मुद्दा जरूर बन गया है, लेकिन इसकी जड़ में युवाओं की वास्तविक बेचैनी है। राजनीतिक दल इस बेचैनी को अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसका स्थायी समाधान राजनीति से नहीं, विश्वसनीय व्यवस्था से निकलेगा। जिस दिन बिहार का छात्र बिना किसी संदेह के परीक्षा केंद्र में बैठेगा कि उसकी मेहनत किसी सिफारिश, लापरवाही या गड़बड़ी से हार नहीं सकती, उसी दिन पेपर लीक की राजनीति की जमीन कमजोर होगी। तब तक सड़क पर आंदोलन भी होंगे, राजभवन मार्च भी होंगे और सत्ता तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी जारी रहेंगे।

संपादकीय

मिठास की खटास

हाल के दिनों में बाजारों में चीनी की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल देखा गया है। वहीं चीनी की कालाबाजारी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने इसकी बिक्री का नियमन भी किया है। साथ ही सरकार ने बिना टैक्स दस लाख टन कच्ची चीनी के आयात की इजाजत देने का भी फैसला किया है। लेकिन सरकार का यह फैसला शायद ही बढ़ती कीमतों का जवाब हो। निस्संदेह, यह परिदृश्य सरकार के लिये उसकी महत्वाकांक्षी इथेनॉल नीति की असलियत को समझने का एक अवसर भी है। पूरे देश में इथेनॉल मिश्रित ई-20 पेट्रोल की बिक्री व्यवस्था लागू करने का जश्न मनाने के दो साल से भी कम समय में सरकार अब दो परस्पर विरोधी जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। पहला, देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिये कच्चे तेल के आयात को कम करना और दूसरा उपभोक्ताओं के लिये सस्ती चीनी उपलब्ध कराना। निस्संदेह,यह घटनाक्रम एक नीतिगत दुविधा को तो दर्शाता है कि जब एक ही फसल का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ और ईंधन, दोनों के लिये किया जाता है, तो किसी एक लक्ष्य को दूसरे से अलग रखकर पूरा नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, ऐसे वक्त में जब खाड़ी संकट के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों का संकट व्याप्त रहा, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ने देश के नागरिकों व सरकार को बड़ी राहत दी है। इसमें दो राय नहीं कि निर्धारित समय सीमा से पहले ही बीस फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य हासिल करके, भारत ने आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कुछ कम जरूर किया है। वहीं दूसरी ओर सरकार की इस अभिनव पहल से जहां एक ओर चीनी मिलों को सहारा मिला है,वहीं गन्ना किसानों के लिये कमाई का एक अतिरिक्त जरिया भी बना है। निश्चित रूप से उस देश के लिये यह एक उपलब्धि ही कही जा सकती है जो अपनी जरूरतों के लिये 85 फीसदी कच्चे तेल का आयात करता रहा है। वह भी अपने देश में उपलब्ध वैकल्पिक संसाधनों के जरिये। इसके बावजूद राजग सरकार की इस रचनात्मक पहल की कुछ बुनियादी खामियां भी हमारे सामने उजागर हुई हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि गन्ना भारत में सबसे ज्यादा पानी की खपत करने वाली फसलों में से एक है। वहीं दूसरी ओर इथेनॉल के उत्पादन के लिये गन्ने का इस्तेमाल ऐसे समय में शुरू हुआ है जब देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में शुमार महाराष्ट्र और कर्नाटक में पैदावार खराब मौसम और गन्ने की फसल पर लगी बीमारियों के चलते कमजोर रही है। यह भी एक वजह है कि गन्ना आपूर्ति में आई कमी के चलते भी हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में तेजी देखी गई है। जिसके चलते सरकार को चीनी का निर्यात रोकना पड़ा है। इतना ही नहीं, सरकार को आसन्न त्योहारी मौसम को देखते हुए अब कच्ची चीनी के आयात को अनुमति देनी पड़ी है। निस्संदेह, इन परिस्थितियों के मद्देनजर यह नहीं कहा जा सकता कि देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग विफल हो गया है। बल्कि यह समझने की जरूरत है कि देश की कृषि संबंधी वास्तविकताओं और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की खाद्य जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि देश में एक लचीली जैव ईंधन रणनीति को तार्किक बनाया जाए। जिसे फसलों की स्थितियों और घरेलू खाद्य जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके। निस्संदेह, फसलों के अवशेष और कृषि अपशिष्ट से निर्मित होने वाले इथेनॉल में अधिक निवेश करने से ही गन्ने पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही जलवायु लक्ष्यों को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। भारत द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के लक्ष्य के रूप में कामयाबी एक सराहनीय उपलब्धि कही जा सकती है। निस्संदेह यह उपलब्धि खाद्य मुद्रास्फीति या जल के अंधाधुंध दोहन की कीमत पर नहीं हासिल की जा सकती। सही मायने में सबसे अच्छी नीति वही मानी जाएगी, जो ईंधन के टैंक और रसोई के भंडार पर्याप्त मात्रा में भरा रख सके।

कश्मीर पर अमेरिकी सुर बदलेः भारत का कद बढ़ा, पाक बेचैन

(लेखक- ललित गर्ग)

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का 19 अगस्त 2026 को श्रीनगर में दिया गया यह बयान कि जम्मू-कश्मीर 'भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा' है, सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी मानकर नजरअंदाज करने योग्य नहीं है। यह ऐसे समय आया है जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान की धारणाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार नए समीकरण बन रहे हैं। गोर ने जम्मू-कश्मीर की निरन्तर सुधर रही सुरक्षा स्थिति की बात कही और अमेरिकी यात्रा संबंधी परामर्श पर पुनर्विचार के संकेत भी दिए। पाकिस्तान ने इस बयान पर अमेरिका के शीर्ष राजनयिक को तलब कर तीखा विरोध दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम को केवल कश्मीर के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसे भारत-अमेरिका संबंधों में आ रहे व्यापक परिवर्तन, दक्षिण एशिया की बदलती सामरिक संरचना और पाकिस्तान की घटती कूटनीतिक प्रभावशीलता के संदर्भ में समझना अधिक उचित होगा।

अमेरिका की कश्मीर नीति में लंबे समय से एक प्रकार की सावधानी रही है। वाशिंगटन सामान्यतः भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद तथा शांतिपूर्ण समाधान की बात करता रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की पूर्व घोषित नीति भी जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति और राजनीतिक-आर्थिक स्थिरता की वापसी का समर्थन करती रही है। इसलिए गोर का श्रीनगर में जाकर जम्मू-कश्मीर को भारत का 卐महत्वपूर्ण हिस्सा卐 कहना निश्चित रूप से भाषा के स्तर पर एक उल्लेखनीय परिवर्तन है। लेकिन इसे अमेरिका की पूरी कश्मीर नीति में तत्काल और औपचारिक परिवर्तन मानना भी जल्दबाजी होगी। किसी राजदूत का बयान और किसी सरकार की औपचारिक नीति में अंतर होता है। फिर भी कूटनीति में शब्दों का अपना महत्व होता है। विशेष रूप से तब, जब वही शब्द उस भूभाग में बोले जाएं जिसे पाकिस्तान दशकों से अंतरराष्ट्रीय विवाद के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। इस दृष्टि से गोर का बयान भारत के लिए मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है।

इस बयान का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जम्मू-कश्मीर की बदलती जमीन से जुड़ा है। गोर ने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का उल्लेख करते हुए यात्रा संबंधी अमेरिकी परामर्श में कमी लाने की संभावना जताई है। इसका अर्थ यह है कि वाशिंगटन अब कश्मीर को केवल सुरक्षा संकट या आतंकवाद की दृष्टि से देखने के बजाय पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों और सामान्य जनजीवन की संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में भी देख रहा है। यहीं से भारत-अमेरिका संबंधों की नई रोशनी दिखाई देती है। दोनों देशों के संबंध अब केवल व्यापार या रक्षा तक सीमित नहीं हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, आपूर्ति-श्रृंखला और वैश्विक शक्ति-संतुलन जैसे विषयों ने भारत को अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार और शुल्क जैसे मुद्दों पर मतभेद भी मौजूद हैं, फिर भी व्यापक सामरिक साझेदारी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है। हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा का उद्देश्य भी तनावों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना और व्यापार तथा ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाना था। इसलिए कश्मीर पर अमेरिकी भाषा को भारत-अमेरिका संबंधों के व्यापक पुनर्संतुलन का हिस्सा मानना अधिक तार्किक होगा। अमेरिका के लिए भारत अब केवल दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति-संतुलन का प्रमुख आधार है। भारत के लिए भी अमेरिका महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति को किसी एक शक्ति के साथ पूर्ण निर्भरता के बजाय रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रखा है। यही कारण है कि भारत अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाते हुए रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और अन्य शक्तियों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखता है। कश्मीर के संदर्भ में यह घटनाक्रम पाकिस्तान के लिए निश्चित रूप से असहज करने वाला है। इस्लामाबाद ने गोर के बयान को अस्वीकार करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और उसका अंतिम निर्धारण होना बाकी है। पाकिस्तान ने इसे अमेरिका की पूर्व स्थिति से विचलन बताते हुए औपचारिक विरोध दर्ज कराया।

पाकिस्तान की समस्या यह है कि वह कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी विदेश नीति का केंद्रीय विषय बनाए रखना चाहता है, जबकि विश्व राजनीति की प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं। आतंकवाद, आर्थिक स्थिरता, चीन का बढ़ता प्रभाव, पश्चिम एशिया का संकट, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाएं आज बड़ी शक्तियों की चिंता के केंद्र में हैं। ऐसे वातावरण में केवल कश्मीर के प्रश्न को बार-बार अंतरराष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तानी कोशिशों की प्रभावशीलता सीमित होती जा रही है। भारत ने दूसरी ओर लगातार यह रेखांकित किया है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े विषय भारत की संप्रभुता और द्विपक्षीय संबंधों के दायरे में आते हैं। गोर का श्रीनगर दौरा स्वयं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि एक प्रमुख अमेरिकी राजनयिक ने जम्मू-कश्मीर की यात्रा की, वहां के निर्वाचित नेतृत्व से मुलाकात की और क्षेत्र की सुरक्षा तथा आर्थिक संभावनाओं पर सकारात्मक टिप्पणी की। यह पाकिस्तान की उस कोशिश के विपरीत है जिसमें वह कश्मीर को केवल विवाद और अस्थिरता के चश्मे से प्रस्तुत करना चाहता है। फिर भी भारत को इस बयान से अत्यधिक उत्साहित होकर यह मान लेने से बचना चाहिए कि अमेरिका ने कश्मीर पर अपनी संपूर्ण नीति बदल दी है। अमेरिका की विदेश नीति परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है और वह भारत तथा पाकिस्तान दोनों के साथ अपने हितों को संतुलित करने की कोशिश करता है। आज भी वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान आतंकवाद-रोध, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान सहित कुछ विषयों में उपयोगी साझेदार है। अतः भारत के लिए इस बयान का वास्तविक महत्व किसी औपचारिक अमेरिकी नीति-परिवर्तन से अधिक उस कूटनीतिक वातावरण में है, जिसमें भारत की स्थिति को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से लिया जा रहा है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। कूटनीति में किसी देश का महत्व केवल इस बात से तय नहीं होता कि कितने देश उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, बल्कि इससे तय होता है कि वैश्विक शक्तियों के हित उसके साथ कितने गहरे जुड़े हैं। आज भारत की आर्थिक क्षमता, विशाल बाजार, तकनीकी सामर्थ्य, लोकतांत्रिक संस्थाएं, युवा शक्ति और सामरिक स्थिति उसे विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती हैं। इसी बदलती वास्तविकता का प्रभाव कश्मीर पर भी दिखाई देना स्वाभाविक है। गोर का बयान इसलिए भारत के लिए एक उपलब्धि से अधिक एक संकेत है-संकेत इस बात का कि जम्मू-कश्मीर को लेकर अंतरराष्ट्रीय विमर्श धीरे-धीरे बदल रहा है। पाकिस्तान के लिए यह चेतावनी है कि केवल पुराने नारों और कूटनीतिक दबाव से वह कश्मीर को विश्व राजनीति के केंद्र में नहीं रख सकता और अमेरिका के लिए यह उसके बदलते हितों के अनुरूप संतुलन साधने की कोशिश है।

इच्छाओं को समर्पित करते जाओ

सभी इच्छाएं खुशी के लिए होती हैं। इच्छाओं का लक्ष्य ही यही है। किंतु इच्छा आपको कितनी बार लक्ष्य तक पहुंचाती है? इच्छा तुम्हें आनंद की ओर ले जाने का आभास देती है, वास्तव में वह ऐसा कर ही नहीं सकती। इसीलिए इसे माया कहते हैं। इच्छा कैसे पैदा होती है? किसी सुखद अनुभव की स्मृति या भूत के प्रभाव से इच्छा पैदा होती है। कुछ सुनने से भी इच्छा जागृत हो सकती है या किसी विशेष स्थान या व्यक्ति के संपर्क से। किसी और व्यक्ति की जरूरत या इच्छा भी तुम्हारी अपनी इच्छा के रूप में पैदा हो सकती है। मान लो कोई भूखा है, तो तुम्हें उसे खिलाने की इच्छा हो सकती है, या कोई तुमसे बात करना चाहता हो तो तुम्हारी भी उससे बात करने की इच्छा हो सकती है। कभी-कभी नियति या कोई घटना जिसमें तुम्हें भाग लेना है, तुममें इच्छा जाग्रत करती है, पर तुम अपने कृत्यों का कारण नहीं जानते।

इच्छाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं, वे तुमसे पूछकर नहीं आतीं। जब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तुम उनका क्या करते हो? यदि तुम सोचते हो कि तुम इच्छाहीन हो जाओ, तो यह भी एक और इच्छा है। मैं एक उपाय बताता हूं- सिनेमा देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है और यह टिकट प्रवेश द्वार पर देनी पड़ती है। यदि तुम उस टिकट को पकड़े रखोगे तो अंदर कैसे जाओगे? उसी प्रकार, यदि तुम किसी कॉलेज में दाखिल होना चाहते हो तो आवेदन पत्र की जरूरत है। उसे भरकर जमा करना पड़ता है। उसे पकड़कर नहीं रख सकते। इसी प्रकार जीवन-यात्रा में भी अपनी इच्छाओं को पकड़कर मत रखो, उन्हें समर्पित करते जाओ। जैसे-जैसे समर्पण करते जाओगे, इच्छाएं भी कम उत्पन्न होंगी। सौभाग्यवान वे हैं जिनमें इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि इच्छा जागृत होने के पहले ही वे तृप्त हैं।

विचार मंथन

संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी का धरना

(लेखक - सनत जैन)

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद मार्ग थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए 6 घंटे से अधिक थाने पर बैठे रहे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गई वह वहां से नहीं उठे। संसद मार्ग थाने में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने पहुंचकर सरकार के ऊपर दबाव बनाया उसको देखकर यही कहा जा सकता है, एफआईआर एक बहाना था निशान गृहमंत्री अमित शाह पर था। राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक होकर राजनीति कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी और सरकार की मुसीबत दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। छात्र आंदोलन जब जंतर मंतर पर चल रहा था तब वह प्रधानमंत्री निवास पर जाकर धरने पर बैठ गए। पैलेट गन से घायल युवक की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस नहीं लिख रही थी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने में सफलता हासिल की। अब जब रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो इसकी जांच भी होगी। उन्होंने यह भी इस धरने से संदेश देने का प्रयास किया है कि जब दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष को एक एफआईआर कराने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, उसके बाद भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करती है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में जो अपराध हो रहे हैं उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उसको लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। देखते ही देखते पूरे देश का माहौल बदल गया है। सरकार ने जो डर और भय का माहौल बनाया था, वह इस तरह से खत्म होगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज देश भर में जगह-जगह जेन,अल्फा, जेन-जेड के साथ-साथ किसान आंदोलन, आरक्षण को लेकर आंदोलन और हर राज्य में आंदोलन विभिन्न वर्गों द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। अब जो आंदोलन हो रहे हैं जंतर मंतर की तरह आंदोलनकारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़ जाते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को यह समझ ही नहीं आता है कि इन प्रदर्शनकारियों से किस तरह से निपटा जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के स्पष्ट निर्देश हैं आंदोलनकारी के ऊपर बल प्रयोग करने में बहुत सावधानी बरती जाए। इससे पुलिस की परेशानी और भी बढ़ गई है। यदि वह बल प्रयोग नहीं करते हैं तो आंदोलनकारियों को खदेड़ना उनके लिए संभव नहीं होता है। वही आंदोलन भी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। इससे सरकारों की परेशानी बढ़ रही है। जिन मामलों को सरकार सामने नहीं आने देना चाहती है, वह बातें अब मीडिया और आंदोलन के जरिए सामने आ रही हैं, जिसके कारण सरकार और भाजपा की छवि दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। रही सही कसर नेशनल चैनल से जो अभी तक सरकार और भाजपा के पक्ष में एजेंडा चलाते थे वहां पर विपक्षी दलों के प्रवक्ता जिस तरह से भाजपा और मीडिया के एंकरों के ऊपर निशाना साध रहे हैं, जिन लोगों को वहां पर बैठाया जाता है वह भी अब भाजपा के प्रवक्ताओं से सवाल पूछने लगे हैं। पिछले एक दशक में जिस तरह के आक्रामक तेवर भाजपा के प्रवक्ता अपनाते थे वही तेवर अब विपक्ष के प्रवक्ता नेशनल मीडिया में अपना रहे हैं। जिसके कारण सरकार और भाजपा को अभी तक मीडिया का जो संरक्षण मिलता था वह संरक्षण भी नहीं मिल पा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो कर्ताधर्ता हैं वह छात्र आंदोलन के साथ-साथ जिस तरह से न्यायपालिका को लेकर मुखर हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, नेशनल बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूरी तैयारी के साथ तथ्यों के साथ जब वहां पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका से जो संरक्षण अभी तक सरकार को मिल जाता था वह संरक्षण भी नहीं मिल पा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास जैसे नेता अब न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उससे न्यायपालिका भी सक्ते में है। राहुल गांधी जब संसद मार्ग थाने में पहुंचे थे, अधिकारियों ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने तथा हाई पावर कमेटी की आड़ में बचने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने।

मजबूरन थाने को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। इसी तरह से जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है उसकी विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में संवैधानिक संस्थाएं भी अपने आप को विचित्र स्थिति में पा रही हैं। ना वह सरकार के पक्ष में काम कर पा रही हैं, किसी तरह से टालमटोल करके मामले को ठंडा करने की जो अभी तक की रणनीति थी वह भी अब सफल नहीं हो पा रही है। आंदोलनकारी अपनी मांगों का निराकरण जब तक नहीं होता है तब तक आंदोलन और धरने को खत्म नहीं करते हैं। जिसके कारण पूरे देश में एक अलग तरीके का वातावरण बनता चला जा रहा है। ऐसा लगता है देश इस समय आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। जो लोग पहले बोलते नहीं थे अब वह भी आंदोलन के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि पिछले 14 सालों में आम जनता के बीच में बनी थी वह छवि अब तेजी के साथ घटती चली जा रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विश्वास था जो अब बड़ी तेजी के साथ अविश्वास में परिवर्तित हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। कर्नाटक सरकार जो नया बिल लेकर आई है उसमें किसी भी सरकारी और सार्वजनिक स्थलों में बिना परमिशन के किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा दिए जाने का सबसे बड़ा असर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं उनके पद संचालन तथा साप्ताहिक और मासिक बैठकों के रूप में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे, कर्नाटक में उसमें एक तरह से रोक लग गई है। अन्य राज्यों में भी इसी तरीके की सुग-बुगाहट शुरू हो गई है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमेरिका कनाडा के 20 अरब डॉलर के आयात पर लगाएगा 50 फीसदी शुल्क

करीबी सहयोगी देशों के संबंध और बिगड़ेंगे

वाशिंगटन ।

अमेरिका ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ता असफल होने के बाद उससे आयात किए जाने वाले 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर शनिवार से 50 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस कदम से ऐतिहासिक रूप से करीबी सहयोगी रहे दोनों देशों के पहले से तनावपूर्ण संबंधों में और खटास आने की आशंका है। एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने बताया कि कनाडा ने इस सप्ताह की शुरुआत में जिन शर्तों पर सहमति बनी थी, उनके आधार पर व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से इनकार कर दिया। ग्रीर ने कनाडा पर नई मांगें रखने और कुछ पुरानी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का आरोप लगाया, जिससे पिछले कुछ दिनों में बनी सहमति का संतुलन बिगड़ गया। इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका की ओर से प्रस्तावित शर्तों में अंतिम समय में किए गए बदलावों को अनुचित और आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बताया। उन्होंने कहा कि ये बदलाव किसी भी समझौते की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। प्रस्तावित आयात शुल्क कनाडा से हर साल अमेरिका भेजे जाने वाले कुल सामान के लगभग पांच प्रतिशत (880 अरब में से 20 अरब डॉलर) पर पड़ेगा, जिसमें हॉकी स्टिक से लेकर टंग डिप्रेसर जैसे उत्पाद शामिल हैं। हालांकि, इसका राजनीतिक असर आर्थिक प्रभाव से कहीं अधिक होने की संभावना है। ये शुल्क पहले बुधवार को लागू होने थे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत जारी रखने के लिए समयसीमा तीन दिन बढ़ा दी थी। इसके बावजूद, दोनों देश तय समय के भीतर किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके।

तनाव के बावजूद भारत पर चीनी मोबाइल ब्रांडों की भारी निर्भरता

- रिपोर्ट के मुता बिक चीन के बाहर भारत इनका सबसे बड़ा बाजार, उत्पादन बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली ।

भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद चीनी मोबाइल ब्रांड भारतीय बाजार पर अपनी भारी निर्भरता बनाए हुए हैं। चीन के बाहर भारत उनके लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसे प्रमुख ब्रांडों के वैश्विक निर्यात में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने उन्हें यहां स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। रिपोर्ट बताती है कि 2025 में वीवो के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 34 फीसदी था। यह ब्रांड भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है, जिसने 2026 की दूसरी तिमाही में कुल बाजार का 18 फीसदी हिस्सा हासिल किया। अब वीवो, डिक्सन टेक्नॉलजीज के साथ संयुक्त उपक्रम के जरिये भारत में अपने स्मार्टफोन उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रही है। वीवो जैसी ही कहानी अन्य चीनी ब्रांडों की भी है। 2025 में ओप्पो के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 23 फीसदी, रियलमी के लिए 35 फीसदी और वनप्लस के लिए 32 फीसदी तक पहुंच गया था। ये चारों ब्रांड (वीवो, ओप्पो, रियलमी और वनप्लस) चीन की दिग्गज कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के स्वामित्व में हैं। मोटोरोला, जिसका नियंत्रण अब चीनी कंपनी लेनोवो के पास है, के लिए भी भारत उसके वैश्विक निर्यात में 20 फीसदी का योगदान देता है और कंपनी भारत में असेंबल किए गए फोन सीधे तौर पर अमेरिका को निर्यात कर रही है। लंदन मुख्यालय वाली स्मार्टफोन निर्माता नथिंग के वैश्विक निर्यात में तो भारत की हिस्सेदारी 71 फीसदी हो गई है। ओएमडीआईए के विश्लेषक संयम चौरसिया के अनुसार, श्याओमी को छोड़कर ज्यादातर चीनी ब्रांड वैश्विक स्तर पर उतने मजबूत नहीं हैं, और चीन के बाद भारत उनके लिए दूसरा सबसे अहम और बड़ा बाजार है, जो उनकी व्यावसायिक सफलता के लिए अपरिहार्य है।

मेटा के एआई कंटेंट मॉडरेशन पर सरकार की चिंता, मानव समीक्षा की वकालत

बिना मानव हस्तक्षेप के एआई द्वारा सामग्री हटाने पर आपत्ति, खालिस्तान मामले का दिया उदाहरण

नई दिल्ली। भारत सरकार ने मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, खासकर उसमें मानव समीक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कंपनी से ऐसे सिस्टम बनाने को कहा है जो सिर्फ एआई इंजन के फैसलों के आधार पर उपयोगकर्ताओं की सामग्री न हटाएं।

वैश्विक दबाव में रहा बाजार- कच्चे तेल और भू-राजनीतिक तनाव ने बढ़ाई अनिश्चितता

हफ्ते के अंत में बाजार ने कुछ सुधार दिखाया, लेकिन अनिश्चितता का माहौल बरकरार रहा

मुंबई ।

बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को उतार-चढ़ाव भरे माहौल का सामना करना पड़ा। पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें शुरुआती दिनों में बाजार पर हावी रहीं, जिससे प्रमुख सूचकांकों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, हफ्ते के अंत में बाजार ने कुछ सुधार दिखाया, लेकिन अनिश्चितता का माहौल बरकरार रहा। कच्चे तेल और भू-राजनीतिक दबाव (सोमवार से बुधवार) हफ्ते की शुरुआत निवेशकों के लिए निराशाजनक रही। सोमवार को भारतीय बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई, जहां सेंसेक्स 281.09 अंक गिरकर 77,728.16 पर और निफ्टी 78.35 अंक गिरकर 24,287.65 पर बंद हुआ। यह लगातार पांचवां कारोबारी सत्र था जब बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी। मंगलवार को भी यह सिलसिला जारी रहा] सेंसेक्स 492.70 अंक गिरकर 77,235.46 पर और निफ्टी 132.75 अंक फिसलकर 24,154.90 के स्तर पर आ गया। बुधवार को भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बाजार में और कमजोरी आई। सेंसेक्स 325.78 अंक गिरकर

76,909.68 पर और निफ्टी 76.60 अंक गिरकर 24,078.30 पर बंद हुआ। इस तरह सेंसेक्स में चार दिनों में कुल 1,170.28 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी ने लगातार सात दिनों तक नुकसान झेला। लंबी गिरावट के बाद गुरुवार को निवेशकों के चेहरे पर खुशी लौटी। अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट और शॉर्ट-कवरिंग के चलते बाजार ने जोरदार वापसी की। निफ्टी ने लगातार सात दिनों की गिरावट के सिलसिले को तोड़ते हुए 24,200 का स्तर पार किया।

आईआईटी हैदराबाद में स्थापित होगा जिंदल स्टील उत्कृष्टता केंद्र

उच्च क्षमता, मूल्यवर्धित और लागत-प्रभावी इस्पात उत्पादों व समाधानों पर केंद्रित होगा

नई दिल्ली ।

जिंदल स्टील (जेएसपीएल) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद ने देश के बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिंग और रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नत इस्पात समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इस महत्वपूर्ण साझेदारी के तहत आईआईटी हैदराबाद परिसर में एक जिंदल स्टील उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य उच्च क्षमता और लागत-दक्षता वाले इस्पात उत्पादों का विकास और प्रचार करना है। यह उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से उच्च क्षमता, मूल्यवर्धित और लागत-प्रभावी इस्पात उत्पादों व समाधानों पर केंद्रित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य डिजाइनरों, सलाहकारों, इंजीनियरों, ईपीसी कंपनियों और उपकरण निर्माताओं के साथ मिलकर उन्नत इस्पात ग्रेड के उपयोग की संभावनाओं को पहचानना और उन्हें बढ़ावा देना है। जिंदल स्टील के एक अे धिकारी ने बताया कि यह साझेदारी भारत के बुनियादी ढांचे, इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च क्षमता और लागत-प्रभावी इस्पात के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर दिया कि आईआईटी हैदराबाद की तकनीकी क्षमता और जिंदल स्टील की विनिर्माण, धातुकर्म तथा इंजीनियरिंग विशेषज्ञता को मिलाकर यह केंद्र विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत, हल्के, तेज और अधिक दक्ष इस्पात समाधान विकसित करेगा।

आरबीआई ने श्रीराम फाइनेंस और प्रॉगफिन पर लगाया लाखों का जुर्माना

निदेशक नियुक्ति, केवायसी और जोखिम वर्गीकरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई

मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ नियमों और निर्देशों का पालन न करने के कारण श्रीराम फाइनेंस कॉर्पोरेशन और प्रॉगफिन पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई के अनुसार श्रीराम फाइनेंस पर 8.10 लाख रुपये और प्रॉगफिन पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो वित्तीय नियमों के अनुपालन में गंभीरता को दर्शाता है। आरबीआई ने श्रीराम फाइनेंस पर निदेशक की नियुक्ति करते समय केंद्रीय बैंक से पूर्व लिखित अनुमति न लेने के लिए जुर्माना लगाया, जिसके कारण प्रबंधन में बदलाव हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपनी ग्राहकों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम वाली श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रणाली बनाने में विफल रही और कुछ ग्राहकों के केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) रिकॉर्ड को निर्धारित समय-सीमा के भीतर केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में अपलोड नहीं कर पाई। वहीं प्रॉगफिन पर खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था (जो नियमों के अनुसार हर छह महीने में एक बार अनिवार्य है) लागू करने में विफल रहने के कारण जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई वित्तीय संस्थाओं के लिए सख्त नियामक अनुपालन के महत्व को रेखांकित करती है।

चीनी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि अनुचित, जमाखोरों पर होगी कार्रवाई- सरकार

इथेनॉल उत्पादन को कीमत वृद्धि का कारण बताने से सरकार का इनकार

नई दिल्ली

सरकार ने चीनी की कीमतों में हालिया बेतहाशा वृद्धि को पूरी तरह अनुचित करार देते हुए उन दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के उपयोग से कीमतों में उछाल आया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने स्पष्ट किया कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है, और बढ़ती कीमतें उद्योग की जमाखोरी का परिणाम हैं। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि घरेलू मांग पूरी होने के बावजूद चीनी उद्योग द्वारा कीमतों में तेज वृद्धि अनुचित है। उन्होंने राज्यों को चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार ने एहतियाती कदम के तौर पर 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है, साथ ही थोक उपभोक्ताओं पर 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से अधिक चीनी के भंडारण पर रोक लगाई है।

चोपड़ा ने स्पष्ट किया कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है। 2025-26 विपणन सत्र में उत्पादन अनुमान 343 लाख टन से

घटकर 306 लाख टन रह जाने के बावजूद, सालाना घरेलू मांग 280-285 लाख टन की तुलना में यह पर्याप्त है। उन्होंने इस तीव्र मूल्य वृद्धि को अनुचित बताया, जिसमें खुदरा कीमतें 48 से 56 रुपये और मिल-स्तर पर 47-48 से 62 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए केवल 28 लाख टन चीनी का उपयोग हुआ है, जिसका अधिकांश हिस्सा अब मक्के से बनता है, अतः कीमत वृद्धि का कोई वास्तविक कारण नहीं है।

सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से त्योहारी मौसम में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

राशन वितरण में आएगा बदलाव, डिजिटल रुपया रोकेगा धोखाधड़ी

रियल-टाइम ट्रैकिंग प्रणाली लीकेज और हेराफेरी को काफी हद तक कम करेगी

नई दिल्ली ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में धोखाधड़ी और सब्सिडी लीकेज पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की खाद्य सब्सिडी अब सीधे लाभार्थियों के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) आधारित डिजिटल रुपया वॉलेट में हस्तांतरित की जाएगी। यह कदम देशभर में लगभग 78.85 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह वितरित होने वाले 19,000 करोड़ रुपये के खाद्यान्न में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। यह उद्देश्य-आधारित डिजिटल सब्सिडी लाभार्थियों को सूचीबद्ध दुकानदारों से खाद्यान्न खरीदने की सुविधा देगी। वे एक सुरक्षित और ट्रैक करने योग्य डिजिटल भुगतान तंत्र का उपयोग कर सकेंगे। रियल-टाइम ट्रैकिंग प्रणाली लीकेज और हेराफेरी को काफी हद तक कम करेगी। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता क्यूआर कोड से, जबकि साधारण मोबाइल वाले ओटीपी-आधारित वाउचर से भुगतान कर सकेंगे। अप्रयुक्त कूपन स्वतः सरकारी खाते में लौट जाएंगे, जिससे फर्जी एंट्री की संभावना समाप्त होगी और राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। गुजरात, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में सफल परीक्षण के बाद, इस सीबीडीसी आधारित प्रत्यक्ष

लाभ अंतरण योजना को अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित सात और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की तैयारी है। यह पहल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश में खाद्यान्न वितरण को अधिक कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

परमाणु ऊर्जा उद्योग ने मांगा पारदर्शी शुल्क ढांचा

निजी भागीदारी के बाद उठाई समान अवसर की मांग

नई दिल्ली ।

परमाणु ऊर्जा उद्योग ने केंद्र सरकार से एक पारदर्शी और पूर्वानुमानित शुल्क ढांचे की मांग की है, ताकि विनिर्माताओं के मुनाफे और प्रतिस्पर्द्धी कीमतों के बीच संतुलन बनाया जा सके। 'भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन एवं विकास विधेयक (शांति) अधिनियम, 2025' के पारित होने के बाद इस क्षेत्र में निजी भागीदारी को हरी झंडी मिल चुकी है। अब उद्योग ने सरकार से यह भी अपील की है कि परमाणु ऊर्जा को बिजली के अन्य स्रोतों के साथ बराबरी पर लाने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। लार्सन ऐंड टुब्रो के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने बताया कि आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के लिए शुल्क बाजार दरों के अनुरूप होने चाहिए और बिजली की अधिकतम समतूल्य लागत 8 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जहां भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) की स्वदेशी तकनीक में औसत शुल्क लगभग 4 रुपये प्रति यूनिट है, वहीं विदेशी तकनीक अधिक महंगी है। परब ने सुझाव दिया कि स्थानीय सामग्री को 100 फीसदी तक बढ़ाने और तकनीकी फीस को 6 से 10 रिएक्टरों में विभाजित करने से विदेशी तकनीक भी फायदेमंद हो सकती है।

प्रधानमंत्री से मिले 20 स्पेस स्टार्टअप के सीईओ, निजी अंतरिक्ष क्षेत्र बढ़ाने पर दिया जोर

वैश्विक प्रतिभा और निवेश आकर्षित करने की संभावना, कृषि-पर्यावरण में नए प्रयोगों पर जोर

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में देश के 20 अग्रणी स्वदेशी अंतरिक्ष स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने निजी क्षेत्र के नवाचार और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में उनके बढ़ते योगदान की सराहना की, जो भारत के तेजी से विकसित हो रहे निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए सरकार के मजबूत समर्थन को रेखांकित करती है। मोदी ने इन उद्यमियों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए बधाई देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र की उपलब्धियां अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के सरकार के दृष्टिकोण को सही ठहराती हैं। उन्होंने जोर दिया कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का तीव्र विकास वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने की अपार संभावनाएँ पैदा कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आईएन-स्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका भी इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित थे। इन स्टार्टअप्स में स्काईरूट एयरोस्पेस, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस सहित कई प्रमुख कंपनियां शामिल थीं, जो रॉकेट, उपग्रह, एविओनिक्स, उन्नत प्रणोदन और अंतरिक्ष मलबे को हटाने जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी प्रगति, दृष्टिकोण और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। उन्होंने सरकारी समर्थन और उद्योग के भीतर बढ़ते सहयोग की विशेष रूप से सराहना की। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप से अपनी प्रौद्योगिकियों के नए अनुप्रयोगों, विशेषकर कृषि और पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रों में, का पता लगाने का आग्रह किया।

उन्होंने युवा छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ जुड़ाव को और गहरा करने की भी बात कही।

त्योहारी सीजन में चीनी का कड़वा वार, कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर

एक महीने में 20 फीसदी का उछाल, इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का डायवर्जन

नई दिन्ली।

त्योहारों से ठीक पहले चीनी के दामों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक महीने में चीनी की कीमतें 20 फीसदी बढ़कर 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है। इसका मुख्य कारण इथेनॉल उत्पादन में गन्ने का अधिक इस्तेमाल बताया जा रहा है, जिसने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। भारत में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसने त्योहारों के मौसम में आम उपभोक्ता को मुश्किल में डाल दिया है। एक महीने पहले 48.18 रुपए प्रति किलो मिलने वाली चीनी अब खुदरा बाजारों में 65 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। यह उछाल ऐसे समय में आया है जब देश में गन्ने की पर्याप्त पैदावार है और सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा रखी है। बावजूद इसके दामों का बढ़ना बाजार के एक अजीब संकट की ओर इशारा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संकट की मुख्य वजह इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का बढ़ता उपयोग है। इथेनॉल कार्यक्रम देश की ऊर्जा सुरक्षा के

लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह चीनी की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। पंजाब में चीनी 65 रुपये प्रति किलो बिक रही है, जबकि मुंबई और भोपाल जैसे शहरों में भी कीमतें 58-63 रुपये प्रति किलो के बीच हैं। गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के आने से चीनी की मांग में तेज़ी आएगी, जिससे सरकार के सामने कीमतों को नियंत्रण में रखने और महंगाई को बढ़ने से रोकने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

मोबाइल विनिर्माण को 62,500 करोड़ का बूस्टर, केंद्र ने नई प्रोत्साहन योजना शुरू की

निर्माताओं को 2.5 से 5 फीसदी तक मिलेगा इंसेंटिव, घरेलू पुर्जों की खरीद पर अतिरिक्त लाभ

नई दिल्ली ।

केंद्र सरकार ने देश में मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारतीय ब्रांडों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी नई योजना की घोषणा की है। मोबाइल फोन निर्माण योजना (स्क्लरू) नामक इस पहल के तहत, सरकार अगले पांच वित्तीय वर्षों (2027 से 2031) के लिए 62,500 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी, जिसका लक्ष्य घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाना और निर्यात को गति देना है। यह योजना भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इस योजना में मोबाइल फोन निर्माताओं को उनके पात्र उत्पादन पर 2.5 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ ही, भारत में प्रमुख पुर्जों और सब-असेंबली की घरेलू खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए 1.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल देश में विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार होगा, बल्कि एक मजबूत स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला भी विकसित होगी।

योजना को दो मुख्य लक्षित खंडों में बांटा गया है- पहला, मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूसरा, भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों को मजबूत करना। इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण सेवा कंपनियां भी शामिल हैं, का भारत में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2026 में उनका कारोबार कम से कम 10,000 करोड़ रुपये होना जरूरी है। यह योजना पिछली सफल नीतिगत पहलों की निरंतरता है, जिनके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2015 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में सात गुना और निर्यात में 11 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

पहले सेगमेंट में पात्र बिक्री पर इंसेंटिव की दर धीरे-धीरे कम होगी, जो वित्त वर्ष 2027 और 2028 में 2.75 प्रतिशत, 2029 और 2030 में 2.5 प्रतिशत, और 2031 में 2.25 प्रतिशत रहेगी। वहीं दूसरे सेगमेंट, जिसका लक्ष्य भारतीय ब्रांडों को सशक्त करना है, में अधिक इंसेंटिव मिलेगा। यह पहले दो साल में 5 प्रतिशत, वित्त वर्ष 2029 और 2030 में 4.5 प्रतिशत, और वित्त वर्ष 2031 में 4 प्रतिशत होगा। अतिरिक्त इंसेंटिव के लिए डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, एनक्लोजर, बैटरी और यूएसबी केबल व कनेक्टर जैसे मुख्य पुर्जे शामिल हैं।

ऑटो सेक्टर में उत्सव का माहौल, चुनौतियों से इनकार नहीं

त्योहारी सीजन से पहले रिकॉर्ड बुकिंग, ऑटो कंपनियों ने बढ़ाया उत्पादन

नई दिल्ली

देश का यात्री वाहन उद्योग त्योहारी सीजन के लिए कमर कस चुका है। रिकॉर्ड बुकिंग और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माता उत्पादन बढ़ा रहे हैं, डीलरों के पास स्टॉक जमा कर रहे हैं और नए मॉडल उतारने की तैयारी में हैं। हालांकि, इस उत्साह के बीच कंपनियों को वित्त वर्ष 2027 की दूसरी छमाही में वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ने का डर सता रहा है, जिसकी वजह पिछले साल के जीएसटी लागू होने के बाद की उच्च बिक्री तुलना है। कमोडिटी की बढ़ती कीमतें और डीलरों के पास बढ़ता स्टॉक भी अतिरिक्त जोखिम पैदा कर रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 74.3 प्रतिशत डीलरों को बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है, जो जुलाई से पहले के 51.24 प्रतिशत से काफी अधिक है। त्योहारी सीजन के लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, और यात्री वाहनों के 53.57 प्रतिशत डीलरों ने बुकिंग में बढ़ोतरी दर्ज की है। आपूर्ति की रुकावटों को दूर कर और नए मॉडल लाने की तैयारी कर कंपनियां इस मांग को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सांख्यिकीय आंकड़े भी इस तेजी की पुष्टि करते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) के अनुसार; जुलाई में यात्री वाहनों का उत्पादन सालाना आधार पर 26.4 प्रतिशत बढ़कर 5,05,520 इकाई हो गया, जबकि थोक आपूर्ति 34.3 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 4,57,810 वाहनों तक पहुंच गई। अप्रैल-जून तिमाही में भी उत्पादन और थोक आपूर्ति में क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 25.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई। खुदरा बिक्री भी मजबूत बनी हुई है; फाडा के अनुसार, जुलाई में खुदरा पंजीकरण में 19.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, थोक आपूर्ति में खुदरा बिक्री की तुलना में तेजी से हुई बढ़ोतरी से पता चलता है कि यह बढ़त त्योहारों के लिए स्टॉक जमा करने की वजह से है। डीलरों के पास मौजूदा स्टॉक फाडा के सुझाए गए 21 दिनों के मुकाबले बढ़कर 33 से 35 दिन तक पहुंच गया है, जिसमें आधे से अधिक डीलरों ने उच्च स्टॉक की सूचना दी है। फाडा ने आगाह किया है कि अगस्त और सितंबर में वृद्धि का श्रेय कम आधार प्रभाव को जाएगा, क्योंकि पिछले साल जीएसटी 2.0 से पहले खरीदारों ने खरीद टाल दी थी। दीवाली और धनतेरस का नवंबर में पड़ना इस साल अक्टूबर की तुलना को और जटिल बनाएगा, जिससे थोक बिक्री के बजाय खुदरा बिक्री ही उद्योग के लिए असली कसौटी होगी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

फीफा ने अर्जेंटीना पर लगाया करोड़ों का जुर्माना और तीन खिलाड़ियों पर बैन

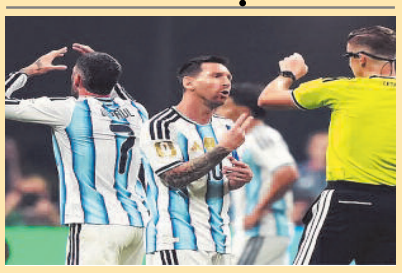

स्पेन (एजेंसी)। फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा ने अर्जेंटीना की फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) अर्जेंटीनी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ पर बड़ा बड़ा जुर्माना लगाया है. फीफा ने उनको ये सजा हाल ही में खत्म हुए फीफा वर्ल्ड कप में की गई गड़बड़ियों की वजह से दी है. जिसमें फाइनल में स्पेन के खिलाड़ी के साथ हुई झड़प भी शामिल है। इस झगड़े की वजह से फीफा ने अर्जेंटीना के चार और स्पेन के एक खिलाड़ी पर जुर्माना लगाया है. अर्जेंटीना के खिलाड़ियों में लिएंड्रो परेडेस को सबसे कड़ी सजा मिली है. इस मिडफील्डर को 10 मैचों के लिए सस्पेंड किया गया है और 90,000 एसडी का जुर्माना लगाया गया है. जबकि नाहुएल मोलिना को 7 मैचों का सस्पेंशन और 90,000 स्ष और थियागो अल्माडा को एक मैच का सस्पेंशन और 30,000 स्ष का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा स्पेन के असिस्टेंट कोच रॉबर्टो अयाला को तीन मैचों का सस्पेंशन और 30,000 स्ष का जुर्माना लगाया गया है. वहीं स्पेन के एक खिलाड़ पाब्लो मार्टिन पेज गाविरा पर एक मैच का सस्पेंशन और 30,000 एसडी का जुर्माना लगाया गया है। खिलाड़ियों के अलावा फीफा ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन पर भी टूर्नामेंट के दौरान हुई कई घटनाओं के लिए 3.64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद खिलाड़ियों का फॉकलैंड आइलैंड्स से जुड़ा पॉलिटिकल बैनर ले जाना और समर्थकों द्वारा भेदभावपूर्ण नारे लगाना शामिल है।

लुसाने डायमंड लीगः नीरज चोपड़ा 9 सेंटीमीटर से चुके पहला स्थान

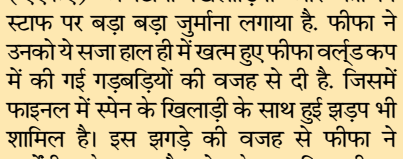

लुसाने (एजेंसी)। नीरज चोपड़ा ने 2026 सीजन का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन वो लुसाने डायमंड लीग में श्रीलंका के रुमेश पथिरागे से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रह गए. जिसकी वजह से उनको दूसरे स्थान पर ही रहना पड़ा।नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में ही 88.05 मीटर का शानदार थ्रो किया, लेकिन पथिरागे ने अपने तीसरे प्रयास में 88.14 मीटर थ्रो करके लुसाने प्रतियोगिता अपने नाम कर ली. ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.69 मीटर की दूरी के साथ तीसरे स्थान पर रहे।दो ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 83.54 मीटर के थ्रो के साथ अपनी शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 88.05 मीटर दूर भाला फेंककर पहले स्थान पर पहुंच गए. लेकिन श्रीलंका के उभरते हुए खिलाड़ी पथिरागे ने तुरंत अपने तीसरे प्रयास में 88.14 मीटर थ्रो करके नीरज से पहले स्थान छीन लिया। चोपड़ा अपने तीसरे थ्रो में केवल 83.72 मीटर ही दूर भाला फेंक पाए और चौथे प्रयास में फाउल कर बैठे. जबकि उन्होंने अपना पांचवां प्रयास नहीं किया. हालांकि, चोपड़ा अपने आखिरी और छठे थ्रो में जरूरी दूरी हासिल नहीं कर पाए।

बांग्लादेश की पहली पारी 64 पर ढेर

बदले की आग में मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, पहले ही दिन गिरे 18 विकेट, ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की मामूली बढ़त

मैके , एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन मामूली बढ़त हासिल कर ली। दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में आठ विकेट पर 165 रन बनाए हैं और उसे अब तक 101 रनों की बढ़त मिली है। स्टंप्स के समय कैमरन ग्रीन 51 और नाथन लियोन 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले, दूसरे ही सत्र में बांग्लादेश की पहली पारी 64 रन पर ऑलआउट हुई। लेकिन शोरिफुल इस्लाम ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार झटके दिए जिससे टीम वापसी करने में सफल रही।

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी

बांग्लादेश को सस्ते में ऑलआउट करने के बाद उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शोरिफुल इस्लाम ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार झटके दिए जिससे उसकी पारी लड़खड़ा गई। शुरुआती झटकों के बाद स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और टीम को बढ़त दिलाई। स्मिथ 42 रन बनाकर आउट हुए और ग्रीन के साथ उनकी साझेदारी टूट गई। इसके बाद एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन ग्रीन टिके रहे और उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। बांग्लादेश के लिए शोरिफुल ने छह विकेट लिए, जबकि तस्कीन अहमद और मेहदी हसन मिराज को अब तक एक-एक विकेट मिले।

पहला सत्र पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम

स्टार्क ने बांग्लादेश की पारी लड़खड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टार्क के आगे बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला गया। इसके बाद पैट कमिंस ने मुशफिकुर रहीम को आउट कर बांग्लादेश को पहले ही सत्र में छठा झटका दिया। बांग्लादेश ने इस तरह 21 रन के स्कोर पर छह विकेट गंवा दिए। लंच तक बांग्लादेश का स्कोर छह विकेट पर 35 रन था।

चार बल्लेबाज खाता खोले बिना आउट

इससे पहले, मैके में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इसे सही साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और बांग्लादेश को झटके पर झटके दिए। स्थिति यह रही कि पहले ही सत्र में बांग्लादेश ने छह विकेट गंवा दिए। मिचेल स्टार्क ने पहली पारी में शानदार गेंदबाजी की और शुरुआत से ही बांग्लादेश पर दबाव बनाया। स्टार्क पहली ही गेंद पर शादमान इस्लाम को पवेलियन भेजा और फिर अपने अगले ओवर की पहली गेंद पर तंजिद हसन तमीम को खाता खोले बिना आउट किया। अगली ही गेंद पर नजमुल हुसैन शांतो स्टार्क का तीसरा शिकार बने। स्टार्क हालांकि, हैट्रिक पूरी नहीं कर सके। स्टार्क ने फिर कैमरन ग्रीन के हाथों मोमिनुल हक को कैच कराया जो नौ रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद स्टार्क का पांचवां शिकार लिटन दास बने जो खाता खोले बिना आउट हुए। बांग्लादेश की बल्लेबाजी इस कदर खराब रही कि चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके।

आग उगलती गेंदबाजी से बांग्लादेश के शीर्ष क्रम बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। स्टार्क ने अपनी शुरुआती 22 गेंदों पर ही पांच विकेट ले डाले। स्टार्क ने 10 ओवर की गेंदबाजी में छह मेडन फेंकते हुए मात्र 12 रन देकर छह विकेट लिए। इस दौरान पांचवां विकेट लेते ही उन्होंने डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया।

दूसरे सत्र में हेजलवुड-कमिंस ने दिखाया दम

लंच ब्रेक के बाद जोश हेजलवुड और कमिंस ने दम दिखाया और दो विकेट झटकर बांग्लादेश को और मुश्किल में डाल दिया। कमिंस ने पहले मेहदी हसन मिराज को आउट किया जो 11 रन बनाकर आउट हुए और फिर हेजलवुड ने हसन महमूद को पवेलियन की राह दिखाई जो 10 रन बनाकर आउट हुए। कमिंस ने इसके बाद तस्कीन अहमद को आउट करने में ज्यादा देर नहीं लगाई और मैट रेनशॉ के हाथों कैच कराकर उनकी पारी का अंत किया। तस्कीन एक रन बनाकर आउट हुए। आखिरी विकेट गिराने के लिए हालांकि, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि तैजुल इस्लाम और शोरिफुल इस्लाम के बीच 10वें विकेट के लिए 25 रनों की साझेदारी हुई। यह बांग्लादेश की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही। इसे स्टार्क ने शोरिफुल को आउट कर तोड़ा। 11वें नंबर पर उतरे शोरिफुल ने बांग्लादेश के लिए पहली पारी में सबसे ज्यादा 14 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क ने छह, कमिंस ने तीन और हेजलवुड ने एक विकेट लिया।

मिचेल स्टार्क ने स्टेन को पीछे छोड़ा ! 19वीं बार टेस्ट में लिए पांच से अधिक विकेट

ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेटों के मामले में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन को पीछे दिया है। स्टार्क अब स्टेन को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट इतिहास के 10वें सफलतम गेंदबाज बन गए हैं। स्टार्क ने शनिवार से साउथ मैके में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच शुरू हुए टेस्ट मैच के पहले दिन यह उपलब्धि हासिल की।

शुरुआती 22 गेंदों पर झटके पांच विकेट

साउथ मैके में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। स्टार्क ने अपनी शुरुआती 22 गेंदों पर ही पांच विकेट ले डाले। स्टार्क ने 10 ओवर की गेंदबाजी में छह मेडन फेंकते हुए मात्र 12 रन देकर छह विकेट लिए। इस दौरान पांचवां विकेट लेते ही उन्होंने डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया।

205 पारियों में 441 विकेट

36 साल के स्टार्क के अब 107 टेस्ट मैचों की 205 पारियों में 441 विकेट हो चुके हैं। स्टार्क टेस्ट मैच की एक पारी में 19 बार पांच या उससे अधिक विकेट ले चुके हैं, जबकि एक मैच में 10 या उससे अधिक विकेट तीन बार ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 58 रन देकर सात विकेट है। स्टार्क से आगे अब वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज कॉर्टनी वॉल्श हैं। वॉल्श के नाम 132 टेस्ट में 519 विकेट हैं। देखना होगा कि स्टार्क इस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं, या नहीं। डेल स्टेन ने 2004 से 2019 के बीच 93 टेस्ट मैचों में 439 विकेट लिए थे। स्टेन अब टेस्ट के सफलतम गेंदबाजों की सूची में 11वें नंबर पर चले गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट श्रीलंका के ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम है। मुरलीधरन ने 1992 से 2010 के बीच 133 टेस्ट में 800 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न हैं। वॉर्न ने 1992 से 2007 के बीच 145 टेस्ट में 708 विकेट लिए थे।

इंग्लैंड के खिलाफ पारी से हारने पर पाकिस्तान टेबल में सबसे नीचे खिसका

नईदिल्ली (एजेंसी)। इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान की दूसरी पारी में सिर्फ 135 रनों पर ही सिमट गई. जिससे उनको पारी और 103 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही मेजबान टीम ने तीन दिन के अंदर ही शानदार जीत हासिल कर ली. पाकिस्तान की हार के लिए मुख्य रूप से रॉबिन्सन जिम्मेदार थे. उन्होंने मैच में 80 रन देकर 8 विकेट लिए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार जीता।

पाकिस्तान टेबल में सबसे नीचे

पाकिस्तान ने पहली पारी में सिर्फ 171 रन बनाए थे. जबकि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 409 रन बनाए. जिससे उनको 238 रनों की बढ़त मिल गई. इसके बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज दूसरी पारी में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के जबरदस्त हमले का सामना नहीं कर सका. जोफ्रा आर्चर, जोश टोंग और ओली रॉबिन्सन ने मिलकर 9 विकेट लिए, जिससे इंग्लैंड ने एकतरफा जीत हासिल की और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकल में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त किए।

इंग्लैंड की यह शानदार जीत जो रूट के फुल-टाइम टेस्ट कप्तान के तौर पर दूसरे कार्यकाल की मजबूत शुरुआत है. इससे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में इंग्लैंड की स्थिति भी बेहतर हुई है. इंग्लैंड की रैंकिंग ऊपर चला गया है, जबकि पाकिस्तान वेस्टइंडीज से नीचे खिसककर 16 पॉइंट्स और 19.05 के पॉइंट्स प्रतिशत (पीसीटी%) के साथ टेबल में सबसे नीचे आ गया है। हालांकि इंग्लैंड स्टैंडिंग में सातवें स्थान पर बना हुआ है. ऑस्ट्रेलिया 77.78 पीसीटी के साथ स्टैंडिंग में टॉप पर बना हुआ है. दक्षिण अफ्रीका भी 75 पीसीटी के साथ स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर है।

पाकिस्तान की करारी हार

मैच की बात करें तो जब पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी शुरू की, तो उन पर भारी दबाव था क्योंकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 238 रनों की बढ़त बना ली थी. मेहमान टीम की मुश्किलें लगभग तुरंत ही शुरू हो गईं जब आर्चर ने अपने पहले ही ओवर में इमाम-उल-हक (0) का विकेट ले लिया।

शान मसूद ने कई बाउंड्री लगाकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड ने दबाव बनाए रखा. इसके बाद अब्दुल्ला शफीक (15) डिफेंस करते हुए एज लगने से आउट हो गए, और लंच से पहले ही पाकिस्तान और भी मुश्किल स्थिति में आ गया।

डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

इसके बाद स्थिति और खराब हो गई जब टंग ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. सबसे पहले सऊद शकील (14) आउट हुए, और फिर इंग्लैंड के इस तेज गेंदबाज ने एक ही ओवर में मसूद (29) और सलमान आगा दोनों को आउट करके पाकिस्तान को हार की कगार पर धकेल दिया।

हालांकि मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाकर कुछ हद तक संघर्ष किया, लेकिन रॉबिन्सन ने दूसरे छोर से कई सफलताएं हासिल कीं. आखिरकार गस एटकिंसन ने रिजवान की पारी का अंत किया और फिर आर्चर ने 38वें ओवर में आखिरी बल्लेबाज को आउट करके मैच खत्म कर दिया।

इससे पहले, पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 171 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें रॉबिन्सन ने 51 रन देकर 5 और टंग ने 46 रन देकर 5 विकेट लिए थे. जवाब में इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के चार बल्लेबाजों ने हाफ-सेंचुरी लगाई. जॉर्डन कॉक्स ने 73, जो रूट ने 66, हैरी ब्रूक ने 91 और डैन लॉरेंस ने 51 रन बनाए. इस मिली-जुली कोशिश से इंग्लैंड ने पहली पारी में 409 रन बनाए, जिससे उनको 238 रनों की बढ़त मिल गई. पाकिस्तान की तरफ से अली उस्मान ने 95 रन देकर 5 विकेट लिए।इस जीत के साथ इंग्लैंड तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे निकल गया है. सीरीज के दूसरा मैच लॉर्ड्स में 27 अगस्त से शुरू होगा।

दो टूक आलोचनाओं पर गौतम गंभीर का जवाब

मेरा काम ट्रॉफियां जीतना है

कोलंबो एजेंसी। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने आलोचनाओं और बाहरी शोर को दरकिनार करते हुए साफ कहा है कि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत के लिए ट्रॉफियां जीतना है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले गंभीर ने कहा कि उन्हें आलोचना, विचारों या लाइक्स की चिंता नहीं है और उनका पूरा ध्यान भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने पर है।

आलोचनाओं पर गंभीर का दो टूक जवाब

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में हार तथा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली शिकस्त के बाद गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठे हैं। हालांकि, इंग्लैंड दौरे पर भारत ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई थी। आलोचनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर गंभीर ने कहा, 'मेरा काम ट्रॉफियां जीतना है। मैं सिर्फ इसी में विश्वास करता हूं और इसी की परवाह करता हूं। यही मेरे और बाकी लोगों के बीच अंतर है। मुझे विचारों या लाइक्स की चिंता नहीं है।'

अगरकर से सिर्फ क्रिकेट पर फोकस

चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर के साथ अपनी बातचीत के बारे में गंभीर ने कहा कि दोनों के बीच चर्चा का मुख्य विषय भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाना और सही फैसले करना होता है। उन्होंने कहा कि बातचीत इस बात पर केंद्रित रहती है कि भारतीय क्रिकेट को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए, क्या महत्वपूर्ण है और खेल की बेहतरी के लिए कौन से फैसले लेने चाहिए।भारत फिलहाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की तालिका में पांचवें स्थान पर है। उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश हैं। हालांकि, गंभीर ने रैंकिंग को लेकर ज्यादा चिंता नहीं जताई। उन्होंने कहा, 'रैंकिंग मायने नहीं रखती। हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे के बाद से हमने संतोषजनक टेस्ट क्रिकेट खेला है।'

कुलदीप यादव का गंभीर ने किया बचाव

दूसरे टेस्ट में टीम संयोजन में बदलाव को लेकर गंभीर ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। हालांकि, उन्होंने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव का समर्थन किया। गंभीर ने कहा कि टीम ऐसी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी इकाई उतारने की कोशिश करेगी, जो 20 विकेट हासिल कर सके। गॉल टेस्ट में कुलदीप ने दोनों पारियों में कुल 25 ओवर गेंदबाजी की थी। उन्हें कम ओवर दिए जाने के सवाल पर गंभीर ने कहा, 'कुलदीप एक अच्छे गेंदबाज हैं और कभी-कभी यह कप्तान पर भी निर्भर करता है।'

सुथार और पडिक्कल के प्रदर्शन को सराहा

पहले टेस्ट में भारत की 165 रन की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले मानव सुथार और देवदत्त पडिक्कल की भी गंभीर ने जमकर सराहना की। पडिक्कल ने मैच में कुल 211 रन बनाए, जबकि सुथार ने गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट हासिल किए। गंभीर ने कहा कि क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके देकर उनका समर्थन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी के बारे में फैसला सिर्फ एक-दो मैचों के प्रदर्शन के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

सलाह दी द्रविड़ ने तीनों प्रारूप में खेलने का किया समर्थन

टेस्ट क्रिकेट को वैभव की जरूरत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट को वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी की जरूरत है। द्रविड़ ने कहा कि सूर्यवंशी को लाल गेंद क्रिकेट के लिए काफी समय और एक्सपोजर की जरूरत है। वैभव सूर्यवंशी इस बार दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की तरफ से खेल रहे हैं। दलीप ट्रॉफी की शुरुआत रविवार से हो रही है। वैभव इस दौरान टीम के उपकप्तान की भूमिका में भी नजर आने वाले हैं।

नई सनसनी बनकर उभरे हैं वैभव

वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की नई सनसनी बनकर उभरे हैं और उन्होंने आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन किया था। वैभव ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया था। वैभव अगले महीने होने वाले एशियाई खेलों के लिए भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। राहुल द्रविड़ जब राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच थे तो राजस्थान फ्रेंचाइजी ने वैभव को आईपीएल नीलामी में खरीदा था। अब द्रविड़ ने वैभव को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार बता दिया है।

द्रविड़ ने यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) के अनावरण के लिए डबलिन में एक इवेंट में कहा, यह बहुत अच्छी बात है कि वैभव को भारत में आईपीएल के जरिए कुछ सीमित ओवर प्रारूप में क्रिकेट खेलने का अनुभव मिल रहा है, लेकिन उन्हें भारतीय घरेलू सिस्टम में वापस जाकर लाल गेंद क्रिकेट खेलने और अपने टेस्ट करियर को आगे बढ़ाने का भी समय मिल रहा है। इस युवा बल्लेबाज को सीमित ओवर और टेस्ट क्रिकेट के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। हम सभी टेस्ट क्रिकेट को जिंदा देखना चाहते हैं और आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। हमें वैभव जैसे खिलाड़ियों की जरूरत है ताकि वे सभी प्रारूप में खेल सकें।

द्रविड़ ने संयम रखने कहा

द्रविड़ ने कहा, अच्छी बात यह है कि उसे कुछ समय लगेगा, उसे कुछ अनुभव की जरूरत होगी। उसे बहुत सारा टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। उसने शायद उतना टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है जितना सीमित ओवर प्रारूप में क्रिकेट खेला है। वह सिर्फ 15 साल का है। मुझे लगता है कि आपको उसे कुछ समय देना होगा और उसके साथ सब्र रखना होगा। जाहिर है वह शुरू से ही बहुत सफल रहा है, लेकिन वह अपने उतार-चढ़ाव से गुजरेगा और मुझे लगता है कि लोगों को उसके साथ सब्र रखना होगा।

वैभव के तीनों प्रारूप में खेलने का भरोसा

द्रविड़ का मानना है कि टी20 मौकों का पीछा करने के बजाय घरेलू टेस्ट क्रिकेट खेलने से बतौर बल्लेबाज वैभव का विकास होगा। उन्होंने कहा, हम सब याद रखें कि वैभव सिर्फ 15 साल के हैं और उन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। मुझे उम्मीद है कि सूर्यवंशी आखिरकार उच्च स्तर पर लाल गेंद क्रिकेट में कदम रख पाएंगे और इंडिया के लिए सभी प्रारूप के खिलाड़ी बन पाएंगे। यह वैश्विक क्रिकेट के लिए उत्साहजनक होगा।मालूम हो कि सूर्यवंशी ने अब तक सिर्फ आठ प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

अमेरिका के अलास्का में चार्टर विमान हुआ क्रैश, दो पायलटों समेत आठ की मौत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के अलास्का में हुए एक बड़े विमान हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई है। पश्चिमी अलास्का में चार्टर विमान क्रैश हो गया और उसमें सवार दो पायलटों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई। अमेरिका की सेना ने सभी आठों लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। एक संघीय अधिकारी ने बताया कि विमान उड़ान भरने के बाद पश्चिमी अलास्का के रिमोट इलाके में रडार से गायब हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि चार्टर विमान ने एंकरेज इलाके से उड़ान भरी थी और गुरुवार दोपहर में वह केप न्यूनहैम इलाके में रडार से गायब हो गया। इसके बाद राहत और बचाव दल विमान की तलाश में जुटा। अब अमेरिकी सेना ने विमान के क्रैश होने की पुष्टि कर दी है और बताया कि विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की है।

टेक दिग्गज अपने बच्चों को सोशल मीडिया से क्यों रखते हैं दूर, दूसरों पर क्या हो रहा असर

वाशिंगटन, एजेंसी। सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान और तेज बनाया है। लेकिन इस तकनीक की दुनिया के बड़े नाम अपने बच्चों के मामले में इसके इस्तेमाल को सीमित रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन लोगों ने डिजिटल दुनिया को इतना बड़ा बनाया, वे अपने बच्चों को इससे क्यों दूर रखना चाहते हैं क्या सोशल मीडिया बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े क्या कहते हैं दुनिया के कई देश बच्चों के लिए सोशल मीडिया की उम्र सीमा तय करने की ओर क्यों बढ़ रहे हैं इन प्लेटफॉर्मस पर कब-कब ऐसे मामले देखने को मिले हैं भारत इस दिशा में क्या कर रहा है मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे लंबे समय तक टीवी या कंप्यूटर के सामने बैठे रहें। उनके अनुसार लोगों के साथ बातचीत करना अच्छी बात है, लेकिन लगातार एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर जाना उतना सकारात्मक नहीं है।

ईरान के ड्रोन हमलों के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, क्यों बंद की यूरोप की अहम यूनिट

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना ने यूरोप में ड्रोन युद्ध की तकनीक पर काम कर रही अपनी एक विशेष यूनिट को बंद करने का फैसला किया है। यह यूनिट पिछले करीब एक साल से ड्रोन बनाने, उनका इस्तेमाल करने और युद्ध के दौरान ड्रोन से लड़ने की रणनीति पर प्रयोग कर रही थी। अब इसे दोबारा एक पारंपरिक एयरबोर्न इन्फैंट्री बटालियन के रूप में काम करने का निर्देश दिया गया है। यह यूनिट इटली और जर्मनी में तैनात 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड का हिस्सा है। पिछले साल नवंबर में करीब 600 सैनिकों की एक बटालियन को विशेष रूप से ड्रोन युद्ध के लिए तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीक और रणनीति विकसित करना था, जिसे जरूरत पड़ने पर किसी भी युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सके। अमेरिकी सेना ने यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध में ड्रोन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से सीख लेने के लिए यह प्रयोग शुरू किया था। यूक्रेन ने युद्ध में कम लागत वाले ड्रोन, खासकर ड्रोन, का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड के सैनिक इटली में एक विशेष ड्रोन लैब में अपने हमलावर ड्रोन भी तैयार कर रहे थे। सेना के मुताबिक, सैनिक ड्रोन के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे ड्रोन विकसित करने पर भी काम कर रहे थे, जिन्हें दुश्मन की जैमिंग तकनीक से बचाया जा सके। अमेरिकी सेना के अधिकारियों के मुताबिक, विशेष ड्रोन यूनिट इस महीने और अगले महीने जर्मनी में होने वाले दो बड़े सैन्य अभ्यासों के बाद अपना प्रयोगात्मक काम पूरा करेगी। इसके बाद यूनिट की ओर से पिछले एक साल में हासिल की गई जानकारी और अनुभव सेना को सौंपा जाएगा। सेना का कहना है कि इन अनुभवों का इस्तेमाल भविष्य में सैनिकों की तैनाती, सैन्य ढांचे और ड्रोन से जुड़ी नई तकनीक के विकास की योजना बनाने में किया जाएगा। इस फैसले की खास बात यह है कि अमेरिकी सेना के लिए ड्रोन युद्ध का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ईरान के साथ युद्ध के दौरान ईरान ने कम लागत वाले शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिकी जहाजों और सैन्य ठिकानों के खिलाफ किया। इन हमलों में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने, एक सेना के हेलिकॉप्टर के गिरने और महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों के इस्तेमाल की बात सामने आई है।

न्यूयॉर्क कैपिटल-टाइम्स स[ायर उड़ाने की थी साजिश: यूएस ने नाकाम किया आईएसआईएस का बड़ा हमला

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अधिकारियों ने अल्बानी स्थित न्यूयॉर्क कैपिटल पर कथित बम हमले की साजिश को नाकाम करते हुए 35 वर्षीय जेसिका बोवी को गिरफ्तार किया है। संघीय जांच ब्यूरो के अनुसार, वह आईएसआईएस के प्रति समर्थन जता चुकी थी, हमले के लिए सरकारी इमारतों की रेकी कर चुकी थी और विस्फोटक को भोजन पहुंचाने की सेवा के जरिए अंदर पहुंचाने की योजना बना रही थी। अधिकारियों ने बताया कि उसे एक निष्क्रिय विस्फोटक और नकली बंदूक दिए जाने के बाद न्यूयॉर्क कैपिटल के पास गिरफ्तार किया गया।

आतंकी संगठन को मदद देने की कोशिश का आरोप : बोवी को गुरुवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद विदेशी आतंकवादी संगठन को मदद पहुंचाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे न्यूयॉर्क की राजधानी अल्बानी की संघीय अदालत में पेश किया गया, जहां एक संघीय मजिस्ट्रेट ने उसे हिरासत में भेज दिया। उसके खिलाफ दायर शिकायत में संघीय जांच ब्यूरो ने कहा है कि करीब पांच साल पहले इस्लाम धर्म अपनाने के बाद बोवी ने कुनिया यानी सम्मानसूचक इस्लामी नाम आयशा सैफ अपना लिया था। सामाजिक माध्यमों पर उसने 2001 में अल-कायदा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 9/11 हमलों के समर्थन में पोस्ट किए थे।

सामाजिक माध्यमों पर

अमेरिका विरोधी बयान : संघीय जांच ब्यूरो के अनुसार, बोवी ने कई अन्य अमेरिका विरोधी टिप्पणियां भी की थीं और आतंकवादी संगठनों के प्रति समर्थन जताया था। एक संघीय जांच ब्यूरो के मुखबिर ने उससे संपर्क किया। अदालत में दाखिल शिकायत के अनुसार, बातचीत के दौरान बोवी ने आतंकवादी हमला करने में रुचि दिखाई। उसने कथित तौर पर मुखबिर से कहा, काफिरों का दिमाग उड़ा देना खूबसूरत है।

आईएसआईएस प्रमुख के प्रति निष्ठा की शपथ का दावा : शिकायत के मुताबिक, अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए बोवी ने विश्वासियों के कमांडर और मुसलमानों के खलीफा, मुजाहिद शेख अबू हाफा अल-हाशिमी अल-कुरैशी के प्रति पारंपरिक इस्लामी निष्ठा की शपथ यानी बयाह पूरी कर ली है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, वह इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन का प्रमुख है।

अल्बानी में सरकारी इमारतों की रेकी : संघीय जांच ब्यूरो की शिकायत के अनुसार, बोवी ने अल्बानी में कई इमारतों की रेकी की। इनमें गवर्नर का कार्यालय भी शामिल था। बाद में उसने न्यूयॉर्क कैपिटल को निशाना बनाने का फैसला किया, जहां राज्य की विधायिका का कामकाज होता है। मुखबिर ने उसकी मुलाकात दो अन्य मुखबिरों से कराई। इन दोनों ने बोवी के समर्थक होने का दिखावा किया और उसकी योजना में मदद करने की पेशकश की।

जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की योजना : शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बोवी ने दोनों से कहा कि वह इमारत को जितना संभव हो सके उतना नष्ट करना और बैठक के दौरान राज्य के सीनेटरों को मारना चाहती है। उसने कहा कि जिस जोखिम का वह सामना कर रही थी, उसके बदले वह केवल एक या दो लोगों को मारना नहीं चाहती, बल्कि इससे कहीं अधिक बड़ा नुकसान करना चाहती है। संघीय जांच ब्यूरो के विशेष एजेंट क्रेग ट्रेमारोली ने पत्रकारों से कहा कि बोवी सिर्फ सांसदों को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वह हमारी सरकार के विनाश की मंशा रखती थी।

टाइम्स स्क्वायर और व्हाइट हाउस भी निशाने पर : अदालत में दाखिल शिकायत के अनुसार, बोवी ने हमले के बाद भाग निकलने और देश से बाहर जाने के लिए विमान पकड़ने की इच्छा जताई थी, हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर पाएगी। उसने धमकी दी थी कि वह वापस लौटकर और हमले करेगी। इनमें नए साल की पूर्व संध्या पर टाइम्स स्क्वायर में हमला भी शामिल था। शिकायत के अनुसार, वह व्हाइट हाउस को भी निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन उसका मानना था कि वहां हमला करना अधिक मुश्किल होगा।

भोजन पहुंचाने वाले थैले में विस्फोटक पहुंचाने की योजना : हमले की कथित योजना के तहत बोवी ने कहा था कि विस्फोटक को खाने की डिलीवरी के सामान के रूप में अंदर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उसने एक भोजन पहुंचाने वाली सेवा से थैला भी हासिल किया था। संघीय जांच ब्यूरो के मुताबिक, जब उसने वह सामग्री खरीद ली।

47 परिवारों को 500 करोड़ रुपये देगा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, मुर्दाघर प्रबंधक ने बेच दिए थे शवों के अंग

बोस्टन, एजेंसी। अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने उन परिवारों को 5.3 करोड़ डॉलर (करीब 500 करोड़ रुपये) देने पर सहमति जताई है, जिनके परिजनों के शवों के अंग चोरी कर काले बाजार में बेचे गए थे। यह मामला स्कूल के पूर्व मुर्दाघर प्रबंधक सेड्रिक लॉज से जुड़ा है। अदालत की मंजूरी मिलने के बाद दो अलग-अलग सामूहिक मुकदमों के निपटारे के लिए यह रकम दी जाएगी। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन जॉर्ज क्यू. डेली और बर्नार्ड एस. चांग ने एक पत्र में लॉज की करतूत को बेहद घृणित और मेडिकल समुदाय के मूल्यों के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई।

47 परिवारों ने किया था मुकदमा : इस मामले में उन 47 लोगों के परिजनों ने मुकदमा दायर किया, जिन्होंने मेडिकल रिसर्च और पढ़ाई के लिए अपने शरीर दान किए थे। हार्वर्ड का कहना है कि वह यह निश्चित तौर पर नहीं बता सकता कि लॉज ने किन-किन दानदाताओं के शवों से अंग निकाले थे। स्कूल ने 2018 से मार्च 2023 के बीच दान किए गए शवों के रिकॉर्ड और संघीय जांच से मिली जानकारी की समीक्षा की। इसी आधार पर संभावित रूप से प्रभावित दानदाताओं की पहचान करने की कोशिश की गई।

दिमाग से लेकर हाथ और चेहरे तक बेचे : लॉज को 2023 में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, वह शवों के अंग चोरी कर उन्हें दूसरे राज्यों में खरीदारों तक पहुंचाने वाले एक भयावह नेटवर्क के केंद्र में था। उसने शवों से दिमाग, त्वचा, हाथ और चेहरे तक निकालकर बेच दिए। एक मामले में उसने एक खरीदार को मानव त्वचा दी थी, जिसका इस्तेमाल चमड़ा बनाकर एक किताब की जिल्द तैयार करने में किया जाना था। अभियोजक ने इसे बेहद भयावह घटना बताया था। लॉज ने अदालत में स्वीकार किया था कि वह शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेजे जाने से पहले उनके अंग निकालता था। हार्वर्ड ने स्पष्ट किया है कि उसने यह काम संस्थान की जानकारी या अनुमति के बिना किया। सेड्रिक लॉज को पिछले साल आठ साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उसकी पत्नी डेनिस लॉज को भी इस मामले में मदद करने के लिए एक साल से कुछ अधिक समय की जेल हुई। इसके अलावा लॉज से शवों के अंग खरीदने वाले छह अन्य लोगों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया और उन्हें सजा सुनाई गई। समझौते के तहत हार्वर्ड प्रभावित परिवारों को भुगतान करने के साथ-साथ एक आधिकारिक बयान भी देगा, जिसमें लॉज के कृत्य की निंदा की जाएगी और मेडिकल स्कूल के शव दान कार्यक्रम में किए गए सुधारों की जानकारी दी जाएगी।

नूर खान एयरबेस पर दिखा तुर्किये का सैन्य विमान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर क्यों बढ़ी हलचल

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान और तुर्किये के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक नई हलचल सामने आई है। मक्का रक्षा समझौते के बाद तुर्किये वायुसेना का एक सैन्य परिवहन विमान पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पहुंचा। विमान 18 अगस्त को वहां पहुंचने और लौटने के दौरान दर्ज किया गया। इसी एयरबेस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय कार्रवाई में निशाना बनाया गया था।

इस घटनाक्रम के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान में तुर्किये की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। एविएशन हिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार तुर्किये वायुसेना का एयरबस ए-400एम एटलस विमान 18 अगस्त को नूर खान एयरबेस पहुंचा और वहां से वापस लौटा। विमान का कॉलसाइन टीयूएएफ526 बताया गया है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, तुर्किये की ओर से उन्नत ड्रोन, हथियार और अन्य सैन्य साजो-सामान पाकिस्तान पहुंचाए जाने की आशंका है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस विमान के जरिए भेजे गए सामान की पूरी सूची सामने नहीं आई है। भारतीय एजेंसियां इस गतिविधि को गंभीरता से देख रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्किये की ओर से पाकिस्तान को सैन्य साजो-सामान दिए जाने की बात सामने आई थी। मई 2025 में पाकिस्तान ने तुर्किये मूल के असिसगार्ड सोंगर और यिहा-3 ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिन्हें भारतीय कार्रवाई में नष्ट किया गया था। पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता को चीन के साथ-साथ तुर्किये के तेजी से विकसित हो रहे रक्षा उद्योग और मानवरहित प्रणालियों से भी जोड़ रहा है। इससे दोनों देशों के रक्षा संबंध भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पाकिस्तान और तुर्किये के बीच ड्रोन तकनीक को लेकर सहयोग पहले भी सामने आता रहा है। मई में पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू ने तुर्किये में बायकर के चेयरमैन सेल्चुक बेराक्तार से मुलाकात की थी। बायकर बायराक्तार टीबी-2, अकिन्जी और केजिलेलेमा जैसे मानवरहित युद्धक विमान विकसित करने वाली कंपनी है।

दो हफ्ते में परमाणु बम बना लेता ईरान, ट्रंप का तेहरान हमलों पर बड़ा दावा, होर्मुज पर कब्जे को लेकर क्या कहा

वॉशिंगट, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े रणनीतिक जलमार्गों पर लगभग नियंत्रण कर रहा है और जल्द ही वहां पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ट्रंप ने कहा, जब हमने बी-2 बमवर्षकों से उन पर हमला किया, तब वे परमाणु हथियार हासिल करने से ठीक दो सप्ताह दूर थे। यही वजह थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा। ट्रंप ने अपने पूर्व निजी वकील माइकल कोहेन के साथ एक साक्षात्कार में ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने यह भी माना कि इस संघर्ष के कारण अमेरिकी लोगों को पेट्रोल और ऊर्जा की अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान के साथ अमेरिका का समझौता करना क्यों हुआ

मुश्किल 77 डब्ल्यूएबीसी रेडियो पर प्रसारित साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, अब ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। हम जलडमरूमध्य पर नियंत्रण कर रहे हैं और जल्द ही पूरा नियंत्रण कर लेंगे। हम ईरान के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बुधवार को जारी साक्षात्कार के इस हिस्से में ट्रंप ने जलमार्गों का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और नेतृत्व को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे बातचीत के जरिए समझौता करना मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने कहा, समस्या का एक हिस्सा यह है कि बहुत से नेता चले गए हैं। समझौता करना आसान नहीं है। कोई नहीं जानता कि नेतृत्व कौन कर रहा है। अमेरिका में बढ़ती ऊर्जा कीमतों पर क्या बोले ट्रंप उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अमेरिकी उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने कहा, और मैं उनसे कहता हूं कि आपकी ऊर्जा की लागत थोड़ी अधिक होगी, पेट्रोल की कीमत भी थोड़ी अधिक होगी। लेकिन हमें मध्य पूर्व का सफर तय करना होगा, क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने दावा किया कि ईरान को सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और उसकी मिसाइलों तथा ड्रोन बनाने की क्षमता काफी कम हो गई है। उन्होंने बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्यकर्मियों को वेतन नहीं मिलने का भी जिक्र किया और इन्हें तेहरान पर बढ़ते दबाव का संकेत बताया। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं इसे फिर से सौ बार करता, वे परमाणु हथियार नहीं रख सकते और उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ बी-2 बमवर्षक विमानों के इस्तेमाल का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान देर रात चलाया गया और हर बम अपने लक्ष्य पर गिरा। उन्होंने कहा, जब हमने बी-2 बमवर्षकों से उन पर हमला किया, तब वे परमाणु हथियार हासिल करने से ठीक दो सप्ताह दूर थे। और यही वजह थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आप उन्हें इस तरह का हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते।

अमेरिका का कर्ज 40 खरब डॉलर के पार: ट्रंप की नीतियों से कितना बढ़ा, ईरान युद्ध और टैक्स कटौती कितनी जिम्मेदार

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज बुधवार को 40 खरब डॉलर के पार पहुंच गया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि बढ़ते वित्तीय दबाव का संकेत भी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय कर्ज खत्म करने का वादा किया था, लेकिन कर्ज लगातार बढ़ता गया। अब उनके दूसरे कार्यकाल में यह उस समय के मुकाबले करीब दोगुना हो चुका है। बढ़ते कर्ज ने अमेरिकी सरकार के सामने खर्च और आय के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बढ़ा दी है। अमेरिकी कर्ज बढ़ने के पीछे कई पुराने और नए कारण हैं। इनमें लंबे

समय से जारी भारी सैन्य खर्च, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर बढ़ता खर्च शामिल है। इसके अलावा 2025 में लागू टैक्स कटौतियों से सरकारी राजस्व पर भी दबाव पड़ा। ईरान युद्ध और उससे जुड़े सैन्य अभियानों ने इस बोझ को और बढ़ाया है। दी गई जानकारी के अनुसार, अकेले इस साल अमेरिका को अपनी देनदारियां पूरी करने के लिए दो खरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज लेना पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि कुल घाटे का करीब आधा हिस्सा निवेशकों को दिए जाने वाले ब्याज में जा रहा है।

क्या ब्याज का बढ़ता बोझ अमेरिका को कर्ज के जाल में फंसा रहा : बढ़ते कर्ज के साथ उसका ब्याज भी सरकार के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पुराने कर्ज पर निवेशकों को ब्याज देना पड़ता है और कर्ज बढ़ने के साथ यह खर्च भी बढ़ता जाता है। इससे सरकार के पास दूसरे जरूरी कामों के लिए उपलब्ध पैसा सीमित हो सकता है। दी गई जानकारी के मुताबिक, कमेटी फॉर ए रिस्पांसिबल फेडरल बजट के वरिष्ठ नीति निदेशक मार्क गोल्डवेन ने चेतावनी दी कि अमेरिका कर्ज के जाल में फंसता नजर आ रहा है। उनके अनुसार, कर्ज कम करने में नीति निर्माताओं की असमर्थता लंबे समय का जोखिम बढ़ा रही है। ट्रंप ने सत्ता में लौटने के बाद सरकारी खर्च कम करने के लिए एलन मस्क के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग बनाया था। इसका लक्ष्य सरकारी खर्च में एक खरब डॉलर तक की कटौती करना था। हालांकि, दिए गए विवरण के अनुसार यह विभाग बचत के मामले में अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर सका। स्थिति इसलिए भी कठिन है क्योंकि चुनाव नजदीक आने के कारण सरकार के लिए बड़े और कड़े फैसले लेना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है।

सीरिया में तुर्किये की सैन्य विस्तार योजना पर इस्राइल की चेतावनी, राजदूत बोले- हद पार कर दी गई है

यरुशलम, एजेंसी। अमेरिका में इस्राइल के राजदूत येचिएल लेइटर ने कहा है कि इस्राइल को स्पष्ट खुफिया जानकारी मिली थी कि तुर्किये सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी का बड़े स्तर पर विस्तार करने की योजना बना रहा है। उन्होंने इसे हद पार करना बताया। द यरूशलम पोस्ट के साथ बातचीत में लेइटर ने कहा, हम तुर्किये या सीरिया में से किसी के साथ तनाव बढ़ाना या युद्ध नहीं चाहते। लेकिन एक हद पार की गई है।

उनकी यह टिप्पणी इस्राइल द्वारा सीरिया में किए गए हवाई हमलों के बाद आई है। इन हमलों की सीरिया और तुर्किये दोनों की सरकारों ने आलोचना की थी। लेइटर ने कहा, यह तुर्किये की ओर से समझौतों का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा था। जिन लोगों को खुफिया जानकारी दी जानी जरूरी थी, उन्हें वह जानकारी मिल गई। जिन्हें पता होना चाहिए था कि क्या होने वाला है, उन्हें इसकी जानकारी थी। हमने स्पष्ट कर दिया था कि यह हमारे समझौतों का उल्लंघन है और इसी वजह से इस्राइल ने कार्रवाई की।

तुर्किये पर इस्राइल ने लगाए क्या आरोप : लेइटर के मुताबिक, मंगलवार को अलेप्पो के पास सीरिया में अबू अल-दुहूर एयरबेस पर इस्राइल ने जो हमला किया, वह कथित तुर्किये के कदम को लेकर दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिए जाने के बाद किया गया। सीरियाई अधिकारियों ने कहा था कि एयरफील्ड पर कम से कम आठ हमले हुए। बाद में सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा था, इस्राइल ने संदेश स्पष्ट कर दिया है- ऐसा मत करो। लेइटर ने कहा कि तुर्की का कथित कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के दौरान इस्राइल और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के प्रशासन के बीच बनी समझ के खिलाफ था। इस समझ के तहत सीरिया में मौजूदा स्थिति को स्थिर रखा गया था।

क्या सीरियाई इलाके पर कब्जा कर रहा तुर्किये : उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में पेरिस में हुई एक बैठक के दौरान भी इन समझों की पुष्टि की गई थी। बैठक में सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी, अमेरिका के सीरिया मामलों के दूत टॉम बैरक, लेइटर, तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख गिल रीच और नेतन्याहू के सैन्य सचिव रोमन गोफमैन शामिल हुए थे। गोफमैन अब मोसाद के निदेशक हैं। लेइटर ने कहा, इस रोक का मतलब है कि जिस तरह तुर्क आगे नहीं बढ़ते, उसी तरह हम भी आगे नहीं बढ़ते और वे हमें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस्राइल सीरिया में सुरक्षा क्षेत्र के तहत केवल 78 वर्ग मील क्षेत्र में मौजूद है, जबकि तुर्की ने पिछले कई वर्षों में उत्तरी सीरिया में 3,500 वर्ग मील क्षेत्र पर धीरे-धीरे कब्जा बढ़ाया है। यह सीरिया के करीब पांच प्रतिशत क्षेत्र के बराबर है। लेइटर ने कहा कि अमेरिका के सीरिया मामलों के दूत और तुर्किये में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक को छोड़कर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने सीरिया में इस्राइली हमले की निंदा नहीं की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन की नीति पहले तय की गई स्थिति को बनाए रखने की है और इसी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमले की निंदा नहीं की। तनाव के बावजूद लेइटर ने कहा कि इस्राइल का मानना है।

बॉस, याद है जब मैं आपके साथ था- ट्रंप-कोहेन की दुश्मनी खत्म, रेडियो शो में फिर दिखी 15 साल पुरानी दोस्ती

वाशिंगट, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को अपने पुराने सहयोगी और बाद में कट्टर आलोचक बने माइकल कोहेन के रेडियो शो में शामिल हुए। यह मुलाकात इसलिए बेहद चौंकाने वाली रही, क्योंकि कभी कोहेन ने ट्रंप को चीटो-डस्टेड कार्टून विलेन तक कहा था और अदालत तथा कांग्रेस के सामने उनके खिलाफ गवाही दी थी। लेकिन अब दोनों के बीच रिश्ते फिर से सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। कोहेन ने ट्रंप के गंदे कामों को छिपाने में अपनी भूमिका के लिए जेल की सजा काटी थी। ऐसे में कुछ साल पहले तक इस तरह की सार्वजनिक सुलह की कल्पना करना भी मुश्किल था।

रेडियो शो में दिखी पुरानी दोस्ती की झलक : कोहेन के 77 WABC रेडियो कार्यक्रम पर यह इंटरव्यू गुरुवार शाम प्रसारित हुआ, जबकि इसका पूरा प्रसारण रविवार को होना है। बातचीत का माहौल बेहद दोस्ताना रहा और दोनों ने अपने उतार-चढ़ाव भरे अतीत का केवल हल्के अंदाज में जिक्र किया। ट्रंप ने कोहेन से कहा, उन्होंने तुम्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जैसा शायद ही किसी और के साथ हुआ हो। उन्होंने आगे कहा,मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि तुमने अपनी कही हर बात वापस ले ली। तुमने बहुत बड़ी बात की है।

कोहेन ने मांगी फिर से माफी : रेडियो इंटरव्यू से कुछ समय पहले सीएनएन से बातचीत में कोहेन ने बताया कि उन्होंने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से माफी के लिए फिर से आवेदन किया है। पिछली सरकार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। कोहेन ने कहा कि शुक्रवार को इस मुद्दे पर फिर बातचीत होने की उम्मीद है। ट्रंप के साथ सुलह ने कोहेन को उन पूर्व सहयोगियों की लंबी सूची में ला खड़ा किया है, जिनके राष्ट्रपति से कभी तीखे मतभेद हुए, लेकिन बाद में रिश्ते फिर सुधर गए। एलन मस्क और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैंटिस इसके हालिया उदाहरण हैं।

15 साल की दोस्ती फिर आई सामने : कोहेन और ट्रंप का रिश्ता हालांकि

इन सभी मामलों से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत रहा है। कभी कोहेन कहा करते थे कि वह राष्ट्रपति के लिए गोली खा सकते हैं। ट्रंप के राजनीतिक सफर के दौरान वह उनके बेहद भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल थे। बाद में दोनों के बीच ऐसा टकराव हुआ कि 2024 के आपराधिक हश-मनी मामले में कोहेन की गवाही ट्रंप को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण साबित हुई। उस समय ट्रंप अपनी राजनीतिक वापसी की कोशिश कर रहे थे। कोहेन ने गुरुवार को कहा कि पिछले एक साल में उनकी और राष्ट्रपति की कई बार बातचीत हुई है। उन्होंने अपने फैसले को समझाते हुए कहा,माफ करने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ भूल जाना। इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो हुआ, वह हुआ ही नहीं। इसका अर्थ है यह तय करने की हिम्मत रखना कि बीता हुआ कल आने वाले कल को तय नहीं करेगा।

बॉस, याद है जब मैं आपके साथ था : इंटरव्यू के दौरान कोहेन कई बार अपने पुराने दिनों को याद करते नजर आए। एक भावुक क्षण में उन्होंने ट्रंप से कहा, बॉस, याद है जब मैं आपके साथ था इस मुलाकात को खास अंदाज में पेश किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 1975 के बैंड वॉर के गीत व्हाई कांट वी बी फ्रेंड्स से हुई और अंत 1978 के पीचेस एंड हर्ब के मशहूर गीत रीयूनाइटेड एंड इट फील्स सो गुड की पंक्तियों के साथ हुआ।

कभी ट्रंप के खिलाफ बने थे अहम गवाह : न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ चले हश-मनी मुकदमे में कोहेन एक महत्वपूर्ण गवाह थे। 2024 में उन्होंने अदालत में गवाही दी कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने उन प्रयासों में अहम भूमिका निभाई थी, जिनका उद्देश्य एक एडल्ट फिल्म अभिनेत्री और पूर्व प्लेबॉय मॉडल के उन दावों को दबाना था, जिनमें उन्होंने ट्रंप के साथ यौन संबंध होने की बात कही थी। कोहेन ने गवाही दी थी कि ट्रंप ने उन्हें पहले किए गए भुगतानों की भरपाई का भरोसा दिया था और उन प्रयासों की जानकारी रखते थे। उन्होंने कहा था, मैं जो कुछ भी कर रहा था, वह मिस्टर ट्रंप के कहने पर और उनके फायदे के लिए कर रहा था। दोनों के रिश्ते में निर्णायक दरार 2018 में पड़ी, जब स्नब्र्झ्रु एजेंटों ने कोहेन के कार्यालय, घर और होटल के कमरे की तलाशी ली। इसके बाद कोहेन ने रूस में ट्रंप टॉवर परियोजना को लेकर कांग्रेस से झूठ बोलने और कैंपेन फंडिंग नियमों के उल्लंघन का अपराध स्वीकार किया। इन मामलों में स्टॉर्मी डेनियल्स और कैरेन मैकडौगल को किए गए भुगतानों का भी जिक्र आया। उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई। बाद में कोहेन ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ गवाही देने के लिए उन पर दबाव डाला गया था।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कभी हां..कभी न.. में अटका बांग्लादेशी पीएम का भारत दौरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत आएंगे या नहीं आएंगे इसको लेकर कभी हांजकभी नज की स्थिति बनी हुई है। वजह ये है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन की तैयारियों के हवाले से मीडिया में खबर आई थी थी तारिक रहमान संभवता भारत आ रहे हैं। जिसकी तैयारियां चल रहीं है। इस तरह की खबरों के बाद ढाका ने बयान जारी कर साफ कर दिया कि फिलहाल ऐसी किसी यात्रा को लेकर किसी योजना को अंतिम रुप नहीं दिया गया है। बता दें कि भारत सरकार ने उन्हें द्विपक्षीय यात्रा के लिए दिल्ली आने का औपचारिक निमंत्रण दिया है, इसके अलावा उन्हें आगामी ब्रिक्स बैठक के लिए भी आमंत्रित किया गया है, हालांकि इन दोनों प्रस्तावों पर अभी आधिकारिक स्वीकृति मिलना बाकी है। दूसरी ओर, राजनीतिक घटनाक्रम के तहत वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। बंगभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री तारिक रहमान सहित कई शीर्ष कैबिनेट मंत्री और सैन्य अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न देशों की ओर से उन्हें बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने की उम्मीद जताई गई है।

तकनीकी खराबी के चलते त्रिची लौटी इंडिगो की सिंगापुर फ्लाइट, 127 यात्री थे सवार

तिरुचिरापल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से सिंगापुर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में शुक्रवार को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी सामने आने के बाद उसे वापस त्रिची एयरपोर्ट लाया गया। विमान में 127 यात्री सवार थे। करीब ढाई घंटे तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद विमान ने रात करीब 9 बजे त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट ने त्रिची एयरपोर्ट से शाम करीब 6:40 बजे सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। कुछ समय बाद विमान में तकनीकी समस्या का पता चला। इसके बाद पायलटों ने विमान को वापस एयरपोर्ट लाने का फैसला किया। सुरक्षित वापसी के लिए विमान ने हवा में चक्कर लगाकर ईंधन कम किया। विमान के हवा में रहने के दौरान त्रिची एयरपोर्ट के अधिकारियों का पायलटों से लगातार संपर्क बना रहा। एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की गई थीं। इसके बाद विमान को वापस त्रिची लाया गया और बिना किसी अप्रिय घटना के उसकी लैंडिंग कराई गई। त्रिची एयरपोर्ट के डायरेक्टर गोपालकृष्णन ने मीडिया को बताया कि तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट करीब ढाई घंटे तक हवा में चक्कर लगाती रही और रात करीब 9 बजे सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पर उतरी। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद 127 यात्रियों को उनके गंतव्य सिंगापुर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजे जाने की बात कही गई है।

झारखंड की सीमेंट फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 3 इंजीनियरों की मौत

रामगढ़ (एजेंसी)। झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्थित मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में काम के दौरान अचानक टरबाइन में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। हादसे में तीन इंजीनियरों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। फैक्ट्री में ब्लास्ट और आग की सूचना मिलते ही फैक्ट्री प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद रामगढ़ से चार-पांच दमकल वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद पावर प्लांट में लगी आग पर काबू पाया। हादसे के बाद देर रात तक फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा। हादसे में मृत हुए लोगों की पहचान रांची निवासी 50 वर्षीय संजीव कुमार केसरी, बोकारो के जगेश्वर बिहार निवासी 25 वर्षीय विनीत महतो और गढ़वा निवासी 24 वर्षीय अभिषेक पांडेय के रूप में हुई है। घायल मजदूर तरुण रजवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर पहुंच गए। ग्रामीणों ने मृत कर्मचारियों के आश्रितों को उचित मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। ग्रामीणों के फैक्ट्री गेट जाम करने की तैयारी की सूचना से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पावर प्लांट यूनिट के इंचार्ज अनुराग त्रिपाठी ने मीडिया के समक्ष हादसे के लिए प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। उनका आरोप है कि प्लांट में तापमान बढ़ने और ओवरहीटिंग के कारण हादसा हुआ। तापमान नियंत्रित करने के लिए उन्होंने प्रबंधन से कई बार एसी लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन इस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने दावा किया कि समय रहते तापमान नियंत्रण की उचित व्यवस्था की जाती तो हादसे को टाला जा सकता था। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

भारत के लिए पाकिस्तान से ज्यादा चीन है चुनौती

पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे का दावा

नई दिल्ली, एजेंसी।

पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने भारत की सुरक्षा चुनौतियों पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जहां एक ओर भारत का ध्यान अब तक सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे के कारण काफी हद तक पाकिस्तान पर केंद्रित रहा है, वहीं दीर्घकाल में चीन कई मोर्चों पर भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धी बनने जा रहा है। अपनी नई पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड- अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज के विमोचन के अवसर पर नरवणे ने स्पष्ट किया कि भारत को बीजिंग के साथ लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने के साथ-साथ एक मजबूत सैन्य प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने चीन के संदर्भ में शत्रु शब्द का उपयोग करने से जानबूझकर परहेज करते हुए प्रतिस्पर्धी शब्द का चुनाव किया, जो दोनों देशों के बीच संबंधों की जटिल प्रकृति को दर्शाता है।

जनरल नरवणे ने स्वीकार किया कि भारत ने पाकिस्तान और चीन, दोनों के साथ ऐतिहासिक युद्ध लड़े हैं और दोनों देशों के साथ सीमाओं पर विवाद आज भी अनसुलझे हैं। इस कारण वे हमेशा भारत के

लिए खतरे और चुनौती के रूप में रडार पर बने रहेंगे। हालांकि, उन्होंने इन दोनों पड़ोसी देशों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के प्रकार में भिन्नता पर जोर दिया। पाकिस्तान से तात्कालिक खतरा मुख्य रूप से उसके द्वारा समर्थित आतंकवाद और लगातार सीमा पार गतिविधियों के कारण है। भारत के पश्चिमी मोर्चे पर सुरक्षा बलों को लगातार हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है, और पाकिस्तान की ये हरकतें देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक सतत चुनौती बनी हुई हैं।

इसके विपरीत, नरवणे ने चीन को आने वाले वर्षों में भारत का मुख्य रणनीतिक प्रतिस्पर्धी बताया। उनका मानना है कि यह प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार और कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में देखी जाएगी। चीन की बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाएं और भारत के साथ उसके क्षेत्रीय विवाद, जैसे कि पूर्वी लद्दाख में जून 2020 की गलवान घाटी झड़प, इस बात का प्रमाण हैं कि बीजिंग के साथ एक लंबी और जटिल प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है। हालांकि अब हालात सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं ने भारत को अपनी सीमाओं पर अत्यधिक सतर्क रहने पर मजबूर किया है। नरवणे, जो 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेनाध्यक्ष रहे, ने इस बात पर विशेष बल दिया कि भारत को चीन के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग के बजाय बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, बल प्रयोग का सहारा लेना हमेशा आखिरी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत को किसी भी संभावित दुस्साहस को रोकने के लिए अपनी सैन्य तैयारी को अविश्वसनीय रूप से मजबूत और विश्वसनीय बनाए रखना होगा। यह एक दोहरी रणनीति है- कूटनीति के माध्यम से शांति की तलाश करना, लेकिन साथ ही किसी भी आक्रामकता का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना। इस रणनीति के तहत, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौता रद्द करने जैसे कई कदम भी उठाए हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में भारत के दृढ़ रुख को दर्शाते हैं। अंततः, नरवणे का बयान भारत की बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करता है, जहां चीन के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना और पाकिस्तान से उत्पन्न खतरों को नियंत्रित करना दोनों ही सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।

तेजस्वी की जनता में साख नहीं, राहुल गांधी की नकल कर रहे : राम कृपाल यादव

पटना (एजेंसी)। बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने राजद नेता तेजस्वी यादव के छात्रों के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की जनता के बीच कोई साख नहीं है और वे राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल ने तंज कसते हुए कहा कि लंबे समय बाद तेजस्वी को छात्रों की चिंता हुई है, वे विदेश यात्रा से लौटकर अचानक मुद्दों पर सक्रिय हुए हैं। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर भी असंतोष पनप रहा है और लोग उनके इरादों पर सवाल उठा रहे हैं। राम कृपाल ने राजद पर निशाना साधकर कहा कि उन्होंने 15 साल के शासन में खजाने की लूट की थी, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन और प्रशासन से बिहार का विकास कर रही है। उन्होंने राजद के वित्तीय संकट वाले बयान को पाखंड करार दिया। मंत्री राम कृपाल ने समाजवादी पार्टी की घेराबंदी कर कहा कि उसका कोई स्टैंड नहीं है, वह कंफ्यूज्ड है और गिरगिट की तरह रंग बदलती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर राम कृपाल ने कहा कि योगी ने अगड़े, पिछड़े, दलित और वंचितों के लिए जाति-पाति से ऊपर उठकर काम किया है, जिससे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है।

जंतर मंतर पर जातिगत आरक्षण और एससी/एसटी एक्ट के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी।

राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गैर-आरक्षित श्रेणी के लोगों और युवाओं ने जाति-आधारित आरक्षण प्रणाली और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकारी सहायता, छात्रवृत्ति और फीस में छूट जैसे लाभ जातिगत पहचान के बजाय पूरी तरह से आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एससी/एसटी एक्ट को रद्द करने की अपील की। उनका तर्क था कि इस एक्ट का लाभ हमेशा समाज के सबसे वंचित वर्गों तक नहीं पहुँचता और इसका दुरुपयोग व्यक्तियों के खिलाफ हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इसके साथ ही, प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण में क्रीमी-लेयर का नियम लागू करने और दशकों पुराने आरक्षण प्रावधानों की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखकर समीक्षा करने की भी मांग की। उनका कहना था कि हालात काफी बदल गए हैं और अब आर्थिक पिछड़ेपन को बिना किसी भेदभाव के हल करने पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। यह विरोध प्रदर्शन आरक्षण सुधार आंदोलन के बैनर तले नीट के छात्र हर्ष दुबे के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इसमें राजस्थान की जनरल सेना, चाणक्य सेना और करणी सेना जैसे संगठन भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी, जिनमें मुख्य रूप से युवा पुरुष थे, अपने हाथों में भगवा झंडे और गरीबों के लिए आरक्षण, जाति के लिए नहीं जैसे नारे लिखे प्लेकार्ड लिए हुए थे। हालांकि, यह प्रदर्शन बिना अनुमति के किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की और शाम को कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आयोजकों को रामलीला मैदान में 500 लोगों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मिली थी, जंतर मंतर पर नहीं।

नितिन नवीन की नई भाजपा टीम के साथ हुई पहली बैठक

आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर किया गया मंथन

नई दिल्ली, एजेंसी।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम के साथ पहली बैठक की। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, संगठन को बूथ और जमीनी स्तर तक मजबूत करने तथा युवाओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के सभी छह अंतरों के गायन से हुई। नितिन नवीन शनिवार को ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें चुनावी राज्यों में संगठन की स्थिति, सरकार और संगठन के बीच समन्वय तथा आगामी राजनीतिक अभियानों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी।

209 दिन बाद हुआ बड़ा संगठनात्मक फेरबदल

नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के 209 दिन बाद 17 अगस्त को 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की गई थी। टीम में 51 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आठ राष्ट्रीय महासचिव हैं। अध्यक्ष पद संभालने के बाद यह नवीन का पहला बड़ा संगठनात्मक फेरबदल माना जा रहा है। नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राम माधव की वापसी हुई है। वहीं वसुंधरा राजे, बैजयंत पांडा और तीरथ सिंह रावत जैसे अनुभवी नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। विनोद तावड़े, सुनील बंसल और अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है।

गोयल और संतोष बरकरार

पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और बीएल संतोष को संगठन महासचिव की जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया है। युवा मोर्चा की कमान हेमांग जोशी को सौंपी गई है। वहीं अमित मालवीय की जगह दीपक म्हास्के को भाजपा आईटी सेल की जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी सूर्या की जगह हेमांग जोशी की नियुक्ति को भी संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। यह फेरबदल 2015 के बाद भाजपा में सबसे बड़े संगठनात्मक बदलावों में से एक है।

सपा प्रमुख का चवन्नी से रुपया वाला बयान अमर्यादित, अशोभनीय और शर्मनाक

मायावती ने समाजवादी पार्टी पर लगाए कई आरोप, कहा-माफी मांगे अखिलेश

लखनऊ, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 'चवन्नी-रुपया' का विवाद गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर राष्ट्रीय लोक दल और बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई हैं। अब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को बहुजन समाजवादी पार्टी की चीफ मायावती का साथ मिल गया है। उन्होंने सपा मुखिया को माफी मांगने को कहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाता दिख रहा है।

मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल व उस पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री के बारे में चवन्नी से रुपया बनाने वाला बयान देना पूरी तरह से अमर्यादित, अशोभनीय और अति-शर्मनाक है। इस प्रकार की अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाज़ी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के परिवार और जाट समाज का अपमान करने के लिए तुरंत

माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वैसे देश की राजनीति में सपा का चाल, चरित्र व चेहरा अपने विरोधी पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी हमेशा से राजनीतिक संकीर्णता व जातिवादी द्वेष आदि से ग्रसित और अविश्वसनीय रहा है, जिस कारण इसका राजनीतिक एवं चुनावी लाभ भी अक्सर मौकों पर बीजेपी उठाती रही है और सेक्युलर ताकतें कमजोर होती रही हैं। मायावती ने कहा कि सपा के अहंकारी रवैये की वजह से पहले भी गठबंधन टूट चुके हैं। उन्होंने 1993 में सपा-बसपा गठबंधन टूटने का जिक्र करते हुए 2 जून 1995 के लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को याद कर कहा कि बाद में अखिलेश यादव ने पुरानी गलतियां न दोहराने का भरोसा देकर बसपा के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, लेकिन चुनाव नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आने के बाद सपा का रवैया फिर बदल गया और गठबंधन टूट गया।

उन्होंने कहा कि बसपा अपने सिद्धांतों और डॉ. भीमराव आंबेडकर के आत्मसम्मान की विचारधारा से समझौता नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन के मामले में केवल अपना काम निकालना जानती है और अपना काम निकलते ही फिर यह पार्टी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है और दूसरी पार्टी के बारे में अनाप-शनाप भाषा का इस्तेमाल करती है, जो कि यह सपा का पुराना रवैया है। ऐसे में सर्वसमाज के लोग सपा की संकीर्ण व जातिवादी राजनीति से जरूर सावधान रहें।

उन्होंने यह भी कहा कि इतना ही नहीं सपा की सभी रही सरकारों में दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों, अपरकास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज का भी काफी शोषण व उत्पीड़न किया गया है और ना ही इनके हितों में कोई भी सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, बल्कि इनकी सरकार में वास्तव में केवल गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अराजक तत्वों का ही भला हुआ है।

ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है : खड़गे

-केंद्र सरकार ने एथेनॉल बनाने में गन्ने का इस्तेमाल होने से किया है इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को चीनी (शक्कर) की बढ़ती कीमतों और कम होते स्टॉक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि त्योहारों से पहले मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट चीनी की मिठास में घुल गई है। खड़गे ने सरकार से सवाल किया कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया। उन्होंने 10 लाख टन चीनी ड्यूटी-फ्री आयात करने की नौबत पर भी सवाल उठाया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने कहा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। भारत सरकार में खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया था कि देश में चीनी की खुदरा कीमत 20 जुलाई के 48 से बढ़कर करीब 56 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि एक्स-मिल कीमत 7-10 दिनों में 47-48 से बढ़कर 62 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल बनाने में गन्ने के इस्तेमाल को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया है। खाद्य सचिव ने कहा कि देश में पर्याप्त चीनी स्टॉक है। कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के पीछे मिलों की ओर से दाम बढ़ाना, जमाखोरी और सट्टेबाजी प्रमुख वजह हैं।

खाद्य सचिव के मुताबिक अब देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब एक-चौथाई हिस्सा ही चीनी से आता है, जबकि बाकी मुख्य रूप से मक्का जैसे अनाज से बनता है। एथेनॉल के लिए डायवर्ट की जाने वाली चीनी की हिस्सेदारी 2022-23 में 12फीसदी थी। यह 2025-26 में घटकर करीब 9फीसदी रह गई है। मौजूदा सीजन में एथेनॉल के लिए सिर्फ 28 लाख टन चीनी डायवर्ट की गई है। इस सीजन में देश में चीनी का उत्पादन 306 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान 343 एलएमटी था। रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों के साथ ज्यादा बारिश से खेतों में पानी भरने के कारण उत्पादन घटा है। मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने तक घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

राजस्थान में 611 स्कूलों के पास अपने भवन ही नहीं, हजारों स्कूलों न टॉयलेट, न पानी

- सीजेपी की टीम गई थी स्कूलों का निरीक्षण करने तो उन पर हुआ था हमला

जयपुर, एजेंसी।

कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल निरीक्षण वाले कदम के बाद राजस्थान सरकार की ओर से जमीनी हकीकत पेश की गई है। प्रदेश सरकार की मानें तो प्रदेश की 611 स्कूलों के पास अपना भवन ही नहीं है। इस मामले में जयपुर की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है तो दूर-दराज के जिलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से प्रदेश के स्कूलों के बारे में जानकारी दी गई।

राजस्थान सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि प्रदेश में 611 सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास अपना भवन ही नहीं है। इनमें 10 बालिका विद्यालय भी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के 64,484 ऐसे सरकारी स्कूल उनमें से 2,047 में शौचालय और 1,049 में पेयजल सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

सरकार के मुताबिक आंकड़े समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2025-26 के यूडीआईएसई डाटा पर आधारित हैं। जयपुर जिले में ही 38 सरकारी स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं। यह मुद्दा ऐसे समय सामने आया है जब सीजेपी की ओर से सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका के नेतृत्व में एक टीम जयपुर के पास बगरू स्थित एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जा रही थी। इसी दौरान टीम पर हमला किया गया। टीम स्कूल को लेकर मिली उस शिकायत की जांच करने जा रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि विद्यालय को गौशाला में संचालित किया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी आंकड़ों में बिना भवन के चल रहे स्कूलों की संख्या के मामले में झालावाड़ सबसे ऊपर है। अकलेरा ब्लॉक में 23, खानपुर में 16 और झालरापाटन में 11 ऐसे स्कूल हैं। इसके अलावा फलोदी के बाप में 11 और बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 10 स्कूल बिना भवन के चल रहे हैं। भवन के बिना चल रहे गर्ल्स स्कूल में जयपुर और अलवर में दो-दो, जबकि बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, करौली, कोटा और राजसमंद में एक-एक स्कूल शामिल हैं। टॉयलेट की कमी वाले स्कूलों में बांसवाड़ा 188 के साथ सबसे आगे है। इसके बाद डूंगरपुर में 124 और उदयपुर में 98 स्कूल हैं। बीकानेर में 84, झालावाड़ में 81 और जैसलमेर में 79 सरकारी स्कूलों में शौचालय सुविधा नहीं है। पेयजल नहीं होने वालों में दौसा 96 स्कूलों के साथ सबसे ऊपर है। उदयपुर में 70, अलवर में 65, करौली में 60 और बांसवाड़ा में 58 स्कूलों में पेयजल सुविधा नहीं है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भवनविहीन स्कूलों और जर्जर भवनों में संचालित स्कूलों के लिए नए भवन बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में भवन, शौचालय आदि उपलब्ध कराना उसकी

सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके अलावा प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक जर्जर स्कूल भवनों के नए निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए हर साल 2,500 करोड़ रुपए और पांच सालों में 12,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने पिछले साल हुए ऑडिट का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में 3,768 सरकारी स्कूल पूरी तरह जर्जर और असुरक्षित घोषित किए गए हैं। उनके मुताबिक ऐसे स्कूलों को बंद या ट्रांसफर किए जाने से नामांकन प्रभावित हुआ है। जूली ने दावा किया कि 83,783 स्कूल कक्ष भी पूरी तरह जर्जर और असुरक्षित हैं।